[Shri K Suryanarayana]

I saw their flags I belong to West Godavari, but I am closely associated with Krishna politics also—it is only 30-40 miles from there

MR DEPUTY-SPEAKER I am afraid we shall have to interrupt the debate now This will continue the next day

---

14.00 hrs.

DISCUSSION ON THE REPORT OF THIRD CENTRAL PAY COMMISSION

MR DEPUTY-SPEAKER We take up the Discussion under rule 193—on the Report of the Third Central Pay Commission (Volumes I to IV) laid on the Table of the House on the 2nd April 1973 Shri Madhu Limaye

SHRI P G MAVALANKAR (Ahmedabad) On a point of order There is no quorum in the House

MR DEPUTY-SPEAKER Let the Bell be rung—Now there is quorum

श्री मधु लिमये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय इस बहस मे मेरा दृष्टिकोण पेशवर ट्रेड यनियन कार्यकर्ता का नही रहेगा । सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय कल्याण चाहने वाले व्यक्ति का यह दृष्टिकोण रहेगा ।

यह जो वेतन आयोग गठित किया गया था वह कोई निष्पक्ष वेतन आयोग नही था । इसके अध्यक्ष और सैक्रट्री आई सी एस के दो सदस्य थे और श्री रघुवर दयाल का जहा तक सवाल है व तो हमेशा कमिटेड जज रहे है । व्यक्तिगत स्वतत्रता बनाम राज्य का भी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया । मैंने देखा कि हमेशा उन्होने सरकार का पक्ष लिया । इसलिए मैं कहता हू कि यह वेतन आयोग एक धोखा मात्र था । 1970 मे इस सदन मे सत्ता कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो गया था और उनको किसी तरह से समय काटना था । समय काटने के लिए उस समय यह वेतन आयोग गठित किया गया था । इसलिए मै कहता हू कि यह कमीशन भी एक कमिटेड कमीशन था और अगर बोलचाल की भाषा मे बोलना है तो एक चमचा कमीशन था । इस कमीशन से न्याय, निष्पक्षता और प्रगतिशीलता आदि गुणो की कम से कम मैं अपेक्षा नही करता था । उनके ऊपर एक दायित्व दे दिया गया था कि सरकार की वे अच्छी तरह वकालत करे और उन्होने अपनी रपट मे उच्च वर्गीय और उच्च वर्णीय स्वार्थों का अच्छा परिचय दिया है । कमिशन के ऊपर जो जिम्मेदारिया सौंपी गई थी मेरी राय मे उन्होने बहुत बढिया ढग से अपनी जिम्मेदारियो को निभाया और उनकी जिम्मेदारी कर्मचारियो का कल्याण करना या राष्ट्रीय हित मे कोई वेतन नीति बनाना तो था ह नही, सरकारी हितो की रक्षा करना यह उनका नियत कार्य था और उन्होने उसको अच्छी तरह से पूरा किया । वेतन कमिशन को वस्तुस्थिति के सामने और आकडो के सामने झुकना पडा है और इन्होने यह कहा है कि सरकारी खर्चे मे वेतन का हिस्सा घटता जा रहा है । उन्होने इस बात को भी माना है कि सरकारी आमदनी और खर्चे के अनुपात मे सरकार का वेतन बिल नही बढा है । आगे चल कर उन्होने यह भी कबूल किया है कि बढी हुई राष्ट्रीय आमदनी मे सरकारी कर्मचारियो को समुचित हिस्सा नही मिला है । कमीशन इस बात को भी मजूर करता है कि सार्वजनिक और निजी

क्षेत्र के मजदूरों की तुलना में सरकारी नौकरों के असली वेतन में भयंकर कटौती हुई है, ग्रीवस फाल, यह खुद कमिशन ने कहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि न्यूनतम वेतन और स्केल निश्चित करते समय कमिशन ने सारे मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों को और प्रस्थापित तत्वों को ठुकरा दिया है। कमिशन कहता है कि निजी क्षेत्र के वेतन मान को सरकारी कर्मचारियों के वेतन मान निश्चित करते समय अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए। कमिशन ने प्रस्थापित सिद्धान्तों को तो अस्वीकार कर दिया लेकिन अपने कोई न्यायसंगत और तर्कसंगत सिद्धान्त कायम नहीं किए। उन्होंने यह कहा है कि चूंकि सरकार सब से अधिक लोगों को रोजगार देती है इसलिए सरकार को अपनी वेतन नीति सुविधा के अनुसार तय करनी चाहिए। मजदूरों का कल्याण, राष्ट्रीयहित समाजवाद के सिद्धान्त, इनका बिल्कुल खयाल नहीं करना चाहिए। कमिशन कहता है कि अपनी सुविधा देखकर सारे काम करो। मैं पूछता हूं कि फिर कमिशन की जरूरत क्या थी। अगर न्यायसंगत और तर्कसंगत कोई बात उस में नहीं रखनी थीं तो वेतन आयोग की मेरी राय में कोई जरूरत ही नहीं थी।

यह सोचने लायक बात है कि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन मान निर्धारित करते समय वेतन आयोग वज्र की तरह कठोर बन जाता है लेकिन जहां प्रथम वर्ग के अफसरों के वेतन मान निश्चित करने का मामला आ जाता है वहां मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम से भी ज्यादा वह मृदु बन जाता है और बड़ी उदारता के साथ प्रथम वर्ग के अफसरों के लिए वेतन मान निश्चित करता है। कमिशन ने यह स्वीकार किया है कि प्रथम वर्ग की आमदनी 1957 के बाद सुधरने लगी और होते होते निजी क्षेत्र के अफसरों तक तकरीबन पहुंच गई। बीच में 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई। उस समय लड़ाई के अवसर पर आई ए एस के लोगों ने अपनी तनख्वाह को अढाई सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक बढ़ा लिया जबकि उस समय दस हजार हमारे सैनिक, हमारे जवान लड़ाई की भूमि पर कुर्बान हो रहे थे। 250 से लेकर 500 रुपये तक किन पदों की तनख्वाह बढ़ाई गई? ज्वायंट सैक्रेट्री, एडीशनल सैक्रेट्री और सैक्रेट्री। उन्होंने देखा कि निजी क्षेत्र में सार्वजनिक धंधों में प्रथम वर्गीय अफसर जो प्रवेश पाते हैं या भरती होते हैं उनको सात सौ रुपया मिलता है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बारे में कहते हैं कि तुलना नहीं करनी चाहिए निजी क्षेत्र से या पब्लिक सैक्टर के सार्वजनिक धंधों से लेकिन प्रथम श्रेणी के अफसरों के वेतन तय करते समय यह कमिशन कहता है कि सरकारी अफसरों को 610 रुपया मिलता है और निजी कम्पनियों में और सार्वजनिक उद्योगों में चूंकि उनको सात सौ रुपया मिलता है इसलिए सीधे नब्बे रुपया बढ़ा देते हैं प्रथम वर्ग के कर्मचारियों का।

समाजवाद के नाम पर लोगों को गुमराह कर के वोट हड़पने वाली इस सरकार के द्वारा नियुक्त कमीशन ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि न्यूनतम और अधिकतम

[श्री मधु लिमये]

वेतन में बीस गुना तक का अन्तर न्यायसगत और समुचित है । समाजवाद के नाम पर वोट लो और कमीशन की रपट में न्यूनतम और और अधिकतम वेतन में बीस गुना का अन्तर, फर्क, समुचित ठहराने का प्रयास करो, यह इस सरकार की दुरगी नीति है । ये लोग दो मुह से बोलते है ।

कमीशन को डर है कि यदि अफसरो के वेतन को घटाया गया, तो गुणवत्ता नीचे चली जायेगी । लेकिन समूचे देश के लिए, सार्वजनिक और निजी उद्योगो के लिए भी, समुचित वेतन नीति तय करने मे हम लोगो ने कोई बाधा नही डाली है । अगर सरकार पूरे देश के लिए वेतन नीति बनायेगी, तो निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र बनाम सरकार, यह झगडा खतम हो जायेगा ।

सरकार की जो भर्ती सम्बन्धी नीति है, उस मे भी मुझे उच्च-वर्गीय और उच्च-वर्णीय दृष्टिकोण नजर आता है । मै कुछ आकडे आप के सामने पेश करना चाहता हू । द्वितीय पे कमीशन के बाद जहा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियो की सख्या 36 प्रतिशत और तीसरे वर्ग के कर्मचारियो की सख्या 112 प्रतिशत बढी है, वहा प्रथम वर्ग के सरकारी अफसरो की सख्या मे करीब करीब 228 फीसदी का इजाफा हुआ है ।

प्रथम वर्ग के कुल 34,000 अफसर है और उसमे 3200, यानी 9 प्रतिशत, आई० ए० एस० के अफसर है । लेकिन बडे पदों में उन का हिस्सा बहुत ज्यादा है । पिताजी के राज्य मे आई० सी० एस० अफसर हावी थे और पुत्री के राज्य मे आई०ए० एस० अफसर हावी है । हो सकता है कि इस कमीशन के चेयरमैन और सैक्रेटरी ने रिपोर्ट मे अपने वर्ग के बालबच्चो का ज्यादा खयाल किया हो, क्योकि आई०सी० एस० अफसरो के बच्चे आगे चल कर आई० ए० एस० बनते है, लेकिन यह तथ्य है कि पिता के राज्य मे प्रशासन पर आई० सी० एस० छा गई थी और पुत्री के राज्य मे आई० ए०एस० छा गई है ।

बडे पदो का बटवारा देखिये । सचिव के पद 45 है, जिन मे से 30 पर आई०ए०एस० के सदस्य है । इसी तरह अतिरिक्त सचिव के 32 पदो मे से 20 पर आई० ए० एस०, सयुक्त सचिव के 169 पदो मे से 86 पर आई० ए० एस० और डायरेक्टर के 138 पदो मे से 81 पर आई० ए० एस० के सदस्य है । डायरेक्टर का पद तो महज आई० ए० एस० के लोगो के लिए चरागाह, ग्रेज़िग ग्राउड, के रूप मे बनाया गया है । जो विशेषज्ञ है, टेकनिकल लोग है, उन के लिए अपने आप को एक आधुनिक सरकार कहने वाली सरकार मे कोई मौका नही है । जिस तरह अंग्रेजो के जमाने मे, और स्वतन्त्रता के पिछले वर्षों मे, आई० सी० एस० के सदस्य सर्वज्ञ माने जाते थे, उसी तरह आज इन्दिरा जी के राज्य मे आई० ए० एस० के लोगों को सर्वज्ञ माना जाता है—वे सब कोई काम कर सकते है ।

न्यूनतम वेतन के निर्धारण मे "समान काम समान दाम" का सिद्धान्त सर्वमान्य है। हमारे सविधान के निदेशक सिद्धान्तो मे उस का उल्लेख है। लेकिन कमीशन ने उस को ठुकरा कर हमारे सविधान की अवहेलना की है। सरकार बुनियादी और मौलिक अधिकारो मे बार-बार परिवर्तन क्यो करना चाहती है? — ताकि सविधान के निदेशक सिद्धान्तो, डायेरेक्टिव प्रिंसिपल्ज, को कार्यान्वित किया जाये। लेकिन इस सरकार को कमीशन खुले रूप से कहता है कि "समान काम समान दाम" के सिद्धान्त को हम नही मानते हैं।

कमीशन की राय मे सरकार को आदर्श मालिक के रूप मे भी एक नजीर पेश करनी चाहिए—वह कहता है कि इस की कोई जरूरत नही है। पद्रहवे त्रिदलीय भारतीय श्रम सम्मेलन का न्यूतम वेतन, नीड-बेस्ड मिनिमम वेज, के बारे मे जो फार्मूला था, कमीशन ने उस को भी अस्वीकार कर दिया है। डा० एक्राइड का डाइट, गिजा, के बारे मे जो सर्वमान्य सिद्धान्त है, उस को भी यह कमीशन कुबूल नही करता है। कमीशन की राय से तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियो को घास खाना चाहिए और प्रथम वर्ग के अफ़सरो को गोश्त, मुर्गा और अ डे का सेवन करना चाहिए। (व्यवधान) मै श्री चह्वाण को कहना चाहता हू कि कमीशन ने यह लिखा है।

कमीशन के मतानुसार निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरो की तुलना नही होनी चाहिए, हालांकि रेलवेज, टेलीफ़ोन और रक्षा मंत्रालय के जिन सस्थानो में बारूद वगैरह बनाने का काम होता, वे सब व्यापारिक सस्थान है। अमरीका मे रेलवे और टेलीफ़ोन निजी क्षेत्र में हैं। पश्चिम के कई राज्यो मे बारूद और हथियार बनाने का काम भी निजी क्षेत्र मे होता है। हम लोगो ने इन सब कामो को सार्वजनिक क्षेत्र मे ले लिया है। लेकिन इस का यह तो मतलब नही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के नाम पर रेल मजदूरो को पीसा जाये और रक्षा मत्रालय के कर्मचारियो को चूसा जाये।

मैं आप से कहना चाहता हू कि आज रेल मजदूरो की हालत बहुत दयनीय है। जो लोग जानते है कि वे लोग किस तरह सर्दी और बरसात मे काम करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से उन लोगो की स्थिति पर दया आयेगी। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है, वेतन कमीशन वज्र की तहर कठोर है, वह उन लोगो की स्थिति की ओर देखना भी नही चाहता है।

चतुर्थ वर्ग, और विशेषतया तीसरे वर्ग, के कुशल मजदूरो आदि के असली वेतन मे जो महगाई के कारण कटौती हुई है। मैं यह टेबल मत्री महोदय को देने के लिए तैयार हू, जिस से प्रकट हो जाता है कि महगाई के कारण असला वेतन मे 5, 10, 20, 25 रुपये से लेकर 200, 250 रुपये तक कटौती हुई है। कमीशन ने 185 रुपये का न्यूनतम वेतन घोषित किया है, लेकिन जो हिसाब

[श्री मधु लिमये]

कमीशन के बहुमत से लगाया है, प्रो० पिलै ने उस को चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि न्यनतम वेतन 196 रुपये होना चाहिए। हम लोगो की राय मे असली वेतन इस मे बहुत कम होगा ।

एक सोचने लायक बात है—श्री चह्वाण इस पर विचार करें—कि रेलवेज मे खलासी, सैकंड फायरमैन, फिट्टर, कुशल फ़िट्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर आदि श्रेणी के जो लोग है, इस कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद वे अपने घर मे जो वेतन, टेक होम पे, ले जायेंगे, उस मे पाच छः रुपये की कटौती होगी। प्राविडेंट फंड को बढ़ा दिया गया है, रिस्क इनशोरेंस का पैसा कटेगा और जो हाउस रेंट कटता है, उस के कारण उन के वेतन मे पाच छः रुपये घटने वाले है । दूसरी श्रेणी के बारे मे यह रकम और ज्यादा हो जाती है । लेकिन जो सब से पीडित और शोषित कर्मचारी है —सैकंड फायरमैन, जिन को हमेशा आग के सामने खडा रहना पडता है, जिन की आखे जल्दी खराब हो जाती है, उन के बारे मे मै विशेष रूप से अर्ज करना चाहता हू ।

बडे बडे अधिकारियो के बारे मे क्या स्थिति है ? मेरे पास तो तीन चार सौ पदो की सूची है । लेकिन मै इस मे समय नही बिगाडना चाहता हू । मैं केवल कुछ उदाहरण देना चाहता हू । कैबिनेट सैक्रेटेरियट मे एस्सिटेंट डायरेक्टर, विजिलेंस की तनख्वाह 300 रुपये बढाई गई है । इसी तरह विजिलेंस इंस्पेक्टर की तनख्वाह 250 रुपये, डिपुटी डायरेक्टर की तन्ख्वाह 400 रुपये, सैक्रेटरी, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की तन्खवाह 300 रुपये; इंस्टीट्यूट आफ सैक्रेटेरियट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर की तन्खवाह 700 रुपये और अतिरिक्त डायरेक्टर की तन्ख्वाह 400 रुपये बढाई गई है । प्रधान मंत्री के सचिवालय मे सोशल सैक्रेटरी की न्यूनतम तन्ख्वाह 350 रुपये और अधिकतम 450 रुपये बढाई गई है ।

सोशल सेक्रेटरी को मैं नही जानता । इसलिये कोई यह न कहे कि मै कोई व्यक्तिगत गुस्सा निकाल रहा हूं । उन का क्या काम है मै नही जानता । शायद हैयर ड्रेसर मे एपाइंटमेंट वह लेते हो । लेकिन साढे तीन सौ और साढे चार रुपये बढ़ाना यह कहा तक तर्क-संगत है ?

नर्सेज की बात लीजिये । तीन दिन मे जब से मेरे नाम से यह प्रस्ताव आया है मै तो तंग आ गया, इतने लोग मिलने आते है। और नर्सेज की स्थिति तो इतनी खराब है . . . . . .

SHRI K P UNNIKRISHNAN (Badagara) There is only one Social Secretary.

श्री मधु लिमये इस का मतलब हैं कि आप समर्थन करते है इस वृद्धि का फिर 4 हजार बढा दिया जाय। बढाइये। अगर यही तर्क है कि एक सोशल सेक्रेटरी है इसलिये साढे तीन सौ और साढे चार सौ तनख्वाह बढा सकते हैं, तो मुझे आप के साथ कोई तर्क ही नही करना है । यह तर्क आप ही को मुबारक हो।

अध्यक्ष महोदय, सभी मंत्रालयों के बारे में तकरीबन यही हालत है। ये आंकड़े तो मिसाल के तौर पर दिये हैं। जो बाद वाले वक्ता हैं वह मुझसे इस को ले जायें, और भी इस में बहुत सी मजेदार बातें हैं।

महगाई भत्ते की बात लीजिये। महगाई का कर्मचारियों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिये, इस सिद्धान्त को सरकार नहीं मानती। दामों को रोकने, दामों को बांधने का काम भी नहीं करती। मैं बहुत ज्यादा महगाई भत्ते के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो दाम बांधने की, दामों को स्थिर करने की बात को ही पसंद करूंगा। लेकिन वह भी ये नहीं कर रहे हैं और एक दफा जो दाम बढ़ जाता है वह फिर कभी नीचे नहीं आता इन के राज में। श्रीमन वृद्धि की 12 महीने की जो यह अवधि रखी गई है और दस प्वाइंट वाली जो शर्त रखी गई है, आप कहते हैं कि दस अब प्वाइंट का सवाल नहीं है। केवल कमीशन ने आधार का साल बदल दिया है। मगर तकरीबन वह दस प्वाइंट ही है और इस में मजदूरों के पैसे की बड़े पमाने पर चोरी हुई है। इसलिये इन्होंने यह 12 महीने का और दस प्वाइंट वाला बखेड़ा खड़ा कर दिया। इंडेक्स नम्बर तैयार करते समय बड़ा घपला हुआ करता है। आप जानते हैं 1963 में बम्बई में इंडेक्स नम्बर को लेकर हम लोग बड़ी लड़ाई लड़े थे। 20 अगस्त, 1963 को पूरा बम्बई शहर बन्द हो गया था। हड़ताल हुई। लकड़ावाला कमेटी बठी। उस ने अपनी सिफारिश की। 8 रुपया उस समय महंगाई भत्ता सभी मजदूरों का बढ़ाया गया था। कई प्रोफेसरों ने कहा कि आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर सारे मजदूरों की वेतन वृद्धि कभी नहीं हुई। ये जो इंडेक्स नम्बर बनाने वाले लोग हैं सरकार के नियंत्रित दामों को लेते है जैसे अनाज, डालडा, कपड़ा, चीनी इत्यादि है और घर का किराया भी। लेकिन वह यह नहीं सोचते हैं कि क्या वास्तव मे इन नियंत्रित दामो पर कर्मचारियो को और मजदूरों को ये सारी चीजें मिलती हैं। नियंत्रित कपडे की बात लीजिये, दस प्रतिशत कपडा नियंत्रित और 90 प्रतिशत अनियंत्रित कपडा बिकता है जिस के दाम एक साल मे 50 प्रतिशत बढ़ गये, 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत। तो यह तो एक धोखा है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि इंडेक्स नम्बर की इस चोरी को रोका जाय और वैज्ञानिक ढंग से इंडेक्स नम्बर को बनाने का काम किया जाय।

दाम वृद्धि दुनिया मे सभी जगह हो रही है, यह बात प्रधान मंत्री के मुह से सुनते सुनते मे तो ऊब गया। इसलिये मैं कुछ आकड़े देना चाहता हू। एक तो पश्चिमी देशों का जीवन स्तर बहुत ऊचा है। लेकिन वहा क्या हुआ यह मैं बताता हूं। यह लंदन एकोनामिस्ट के जुलाई 1973 के अंक से मैंने लिया है — जर्मनी में कन्ज्यूमर प्राइस, उपभोक्ता के दाम, थोक के नही, साढ़े सात प्रतिशत बढ़े हैं। फ्रान्स में साढ़े छः प्रतिशत और ब्रिटेन में 9 प्रतिशत। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों

[श्री मधु लिमये]

में सब से ज्यादा मजदूर हैं। वह तो इतना औद्योगिक इलाका है कि तकरीबन सभी मजदूर हैं। और इसी अवधि में वेतन वृद्धि जर्मनी में 8 प्रतिशत, फ्रांस में 13 प्रतिशित और ब्रिटेन मे साढे 13 प्रतिशित हुई है। इस का मतलब है कि जिस रफ्तार से वहा दाम बढ़े है उस से अधिक तेज रफ्तार से उन की वेतन वृद्धि हुई है। और हमारे यहां क्या स्थिति है ? दाम घोड़ की चाल से और वेतन वृद्धि गधे की चाल से हुई हैं।

सरकारी खर्च में कटौती करने की चर्चा हम लोग एक अरसे से सुन रहे हैं। लेकिन अभी अभी आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर इंसपेक्शन अपना आफिस जामनगर हाउस से साउथ एक्सटेंशन के आलीशान मकान में ले जा रहे हैं। जो मकान पहले नेशनल सीड्स कारपोरेशन ने 8 हजार रुपये मासिक किराये पर लिया था आज शाहनवाज खां का आपूर्ति मंत्रालय उस के लिये 22 हजार रुपये दे रहा है। कोई जरूरत नहीं थी मकान बदलने की। जामनगर हाउस की मरम्मत आठ दस हजार रुपये खर्च करके हो सकती थी। लेकिन नेशनल सीड्स कारपोरेशन जिस के लिये 8 हजार रुपये मासिक किराया देता था उस के लिये यह डाइरेक्टर इन्सपेक्शन 22 हजार रुपया मासिक किराया देने जा रहे हैं। यह भी कोई आई.ए.एस. अधिकारी होंगे क्योंकि ग्रेजिंग ग्राउन्ड उन्ही लोगों के लिये है। क्या इन की यह पैतृक सम्पत्ति है ? क्या वित्त मंत्रालय का इन के उपर कोई नियंत्रण नही है ? मुझे पता चला कि यह चीज बहुत गुप्त रूप से खबर की गई थी। 13 तारीख को सर्कुलर देते है। 14-15 को छुट्टी है और कहते हैं कि 16 तारीख को आफिस शिफ्ट करेगा – कर्मचारियों को मैंने कहा कि हमेशा वेतन और भत्ते की ही बात करोगे। राष्ट्रीय हित की बात करो। वहा थोड़ा हंगामा करो। हम आप के सवाल को उठाएंगे। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने की बात है।

एक माननीय सदस्य : यही करते है, हंगामा मचवाते हैं आप।

श्री मधु लिमये : बिल्कुल करेंगे।

बोनस के बारे में सरकार की कोई नीति नही है। हालाकि इस वेतन आयोग की रपट में यह आता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों और म्युनिसिपैलिटियो के अन्दर जो ट्रांसपोर्ट संस्थान हैं उन को बोनस मिलता है, पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों को बोनस मिलता है। लेकिन रेल और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की नही मिलता। (व्यवधान) .... पब्लिक अंडर टेकिंग्स में तो मिलता ही है, मैं तो म्युनिसिपैल्टियों और राज्यों के कर्मचारियों की कह रहा हूं कि उन को भी मिलता हैं, स्टेट ट्रासपोर्ट, बी.ई.एस.टी. वगैरह को मिलता है ? लेकिन रेल और रक्षा मंत्रालय के सिविलियन एम्प्लाई और डाक और टेलीफोन वाले, इन को नही मिलता। मैं कहता हूं कि रेल मजदूरों का भयंकर नुकसान हो रहा है वेतन कमीशन के चलते और आप लोगों का, रक्षा मंत्रालय वालों का, भी होगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि बोनस के बारे मे सरकार को अपनी कोई तर्कसंगत नीति तय करके सदन के सामने रखनी चाहिये।

इस कमीशन ने राजनैतिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों की चर्चा ही नही की। कहा है कि हम करेंगे भी नही। सबार्डिनेट कार्यालयो के नाम पर आडिटर जनरल के आफिस के साथ कितना अन्याय हुआ। क्या वित्त मत्री यह नही जानते कि संविधान की धारा 148 उप-धारा 5 के तहत उनके लिये कानून और नियम बनाने जरूरी हैं। लेकिन उनके लिये हमने क्या किया? उनका काम बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आडिट के काम को आप पसन्द नही करते हों क्योकि आपकी चोरी उस मे पकडी जाती है, इसलिये उनको मत्रालय के नीचे ला कर रखा। कोई तर्क है?

इसी तरह से मैं इस अवसर पर ससद के सचिवालय के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। सविधान की धारा 98 को देखिये। वैसे तो गिरावट सभी क्षेत्रो मे आ रही है। लेकिन कौन नही जानता है, कौन इस बात को काट सकता है कि राज्य सभा और लोक सभा के सचिवालय के कर्मचारी सभी दिल्ली शहर मे और पूरे देश मे अत्यधिक कार्यक्षम हैं और उनका लोगो के साथ व्यवहार भी ऊंचे दर्जे का है

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. You can criticise the Government, you can point out many things. Here is the Minister and he will reply. But, so far as Lok Sabha is concerned, the Speaker is responsible and he cannot be here to answer your arguments...

SHRI MADHU LIMAYE: I am speaking on the Constitution

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): They are also paid from the Consolidated Fund. Why not the Minister reply?

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you have anything to say about the Lok Sabha Secretariat, you can take it up with the Speaker. Please avoid making any criticism here because there is nobody to give an answer.

श्री मधु लिमये: मैं कोई अनुचित टीका-टिप्पणी नही कर रहा हूं—पिछले 23 वर्षों मे दफा 98 के तहत हम को जो नियम बनाने चाहिये थे, कानून बनाने चाहिये थे, इन के वेतन-मान निश्चित करने चाहिये थे, सविधान की मर्यादा का पालन करना चाहिये था—वह नही किया। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई अनुचित आलोचना नही कर रहा हूं। इन की हालत और वेतन के बारे मे चेयरमैन, अध्यक्ष और सचिवो का उदासीन नही रहना चाहिये—यह मै निश्चित रूप से कहना चाहता हूं।

इस लिये मेरी माग है कि इस सदन की और राज्य सभा के सदस्यो की एक प्रतिनिधिक मिलीजुली कमेटी बने, जो ससद के कर्मचारियो के बारे मे उदार और वास्तविक दृष्टिकोण से अपने सुझाव दे। इस के ऊपर मैं चव्हाण साहब को इस मामले मे वित्त मत्रालय को व्हीटो देने को तैयार नही हूं। सदन का जो फैसला होगा, स्पीकर साहब और चेयरमैन का जो फैसला होगा और हम लोगो की बातो को सुना जायगा, उस को तत्काल कार्यान्वित किया जाय। बडा अन्याय इन सालो मे इन लोगों के साथ हुआ है।

जवानो पर भी पे-कमीशन मेहरबान नही है। आज कल के जवान, इन्फैन्ट्री सोल्जर्स

[श्री मधु लिमये]

सभी तरह के नये हथियारों का प्रयोग करने लगे है, उन में कौशल की जरुरत होने लगी है। सो फिर क्या बात है चव्हाण साहब—चव्हाण साहब भी किसी जमाने में डिफेन्स मिनिस्टर रह चुके हैं—सरकार उन को स्किल्ड वर्कर्स मानने के लिये तैयार नहीं हैं। वे लोग इतनी जोखिम उठाते हैं—यह कोई काल्पनिक जोखिम नहीं है, पिछले कुछ ही वर्षों में कच्छ का मामला आया, भारत-पाकिस्तान की लड़ाई हुई, बंगला देश का मामला आया, चीन के साथ लड़ाई हुई—लगातार जवानों को अपनी जानें जोखिम में डालनी पड़ती हैं। इसलिये कम से कम कुशल कारीगर का दर्जा उन का कुबूल किया जाय और इसी साल उन को वह तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, तो अवधि निश्चित कीजिये, लेकिन सिद्धान्त को मानिये कि जो हमारे सैनिक जवान लोग हैं, ये कौशल-कुशल कारीगर दर्जे के लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कमीशन 1969 में बना। पहली अन्तरिम वृद्धि मार्च, 1970 से लागू की गई, लेकिन अपनी सिफारिशों के बारे में तीन साल इस कमीशन ने निकाल दिये। कई बार आश्वासन दिये कि अगले साल रिपोर्ट आयेगी लेकिन 31 मार्च, 1973 को यह रिपोर्ट आई। बीच के तीन सालों में जो कर्मचारी सेवा-निवृत हो गये, उन की पेन्शनों का ख्याल क्यों नहीं किया गया। पेन्शनरों की जो दयनीय अवस्था है, उस के ऊपर थोड़ा रहम कमीशन और सरकार को करना चाहिये था, लेकिन वह भी नहीं हुआ।

अब जहां तक इम्पलीमेंटेशन का सवाल है—मेरी राय है कि इस की सिफारिशों को 1 मार्च, 1970 से या कम से कम द्वितीय साल के हिसाब से 1 अप्रैल, 1970 से इस को निश्चित रूप से लागू करना चाहिये।

अब आप इन्क्रीमेंन्टल स्केल की बात को लीजिये। तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों के लिये बहुत कम इन्क्रीमेन्टल स्केल हैं, जब कि प्रथम वर्ग के लाडिले अफसरों के लिये इन्क्रीमेंन्टल स्केल 3.3 से लेकर 8 प्रतिशत तक यानी 40 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हैं। जो छोटे कर्मचारी हैं उन के काम के घन्टे भी बढ़ा दिये गये हैं। ट्रेड यूनियनों के द्वारा हमेशा मांग की गई है कि प्वाइन्ट-टु-प्वाइन्ट फिक्सेशन हो, लेकिन द्वितीय पे-कमीशन से भी यह कमीशन पीछे चला गया।

कैजुअल लेबर की बात को लीजिये—अस्थायी कामों के लिये कैजुअल लेबर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है—इस अफसरशाही के चलते ऐसा हो रहा है। लेकिन इन कैजुअल लेबरर्स के साथ भी इस कमीशन ने कोई न्याय नहीं किया। वर्षों की सेवा के बाद भी वही स्थिति रहती है। काट्रेक्ट लेबर की तो चर्चा ही नहीं की है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त हैं कि कांट्रेक्ट लेबर खत्म होनी चाहिये, लेकिन उन का भी कोई उल्लेख इस कमीशन ने कहीं किया। इस-लिये इन सारे प्रश्नों को लेकर कमीशन ने अपनी दकियानूसी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। कमीशन कहता है कि स्वयंचालित मशीनों का उत्तरोत्तर इस्तेमाल होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इन शब्दों के प्रयोग से बेकारी बढ़ाने के काम में, जो पवित्र काम है, कमीशन ने हाथ बंटाया है।

प्रथम वर्ग के अफसरों के लिये भत्ते के रूप में 100 रुपये माहवार की वृद्धि हुई है । इसी तरह से उन को मिलने वाली सेवा निवृत्ति पेन्शन में 155 रुपये से 325 रुपये तक की वृद्धि की गई है । कमीशन ने उन की ग्रैचुइटी में 6 हजार रुपये की वृद्धि कर उस को 30 हजार रुपये तक बढ़ाया है—6 हजार रुपये बढ़ा कर 30 हजार रुपये पर लाकर रखा है । इसी तरह से उन को अन्य वृद्धियों और सुविधायें भी प्रदान की गई हैं । कमीशन और सरकार "काम करो", "पैदावार बढ़ाओ" सभ्यता को प्रस्थापित नहीं करना चाहती है, वह केवल 'आदेश दो" सभ्यता को सुपरवाइजरी-सिविलाइजेशन को हमारे देश में बढ़ाना चाहती है । सरकार के दृष्टि कोण मे कब परिवर्तन आयेगा, यह समझ मे नही आता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अफसर वित्तीय सस्थाओं से कर्जा लेकर मकान बनाते है —1966 मे घर मत्री कौन थे ? श्री मेहर चन्द खन्ना थे—उन्होने छूट दे रखी थी—वे सरकारी क्वाटरो मे रहते है और वित्तीय सस्थाओ से पैसा लेकर मकान बनवाते हैं और फिर विदेशी कम्पनियो को, बड़ी बड़ी कम्पनियों को ऊचे किराये पर दे देते हैं लेकिन जो छोटे कर्मचारी है उन को मकान भी नही मिलते है ।

किरायो मे जो वृद्धि हुई है—उस का कमीशन ने बिलकुल ख्याल नही किया है उल्टा हाउस रेन्ट एलाउन्स को घटाया है । इतना ही नही सिटी-कम्पेनसेटरी एलाउन्स मे कटौती की है हालाकि महगाई तेजी मे बढ़ रही है । इन कारणों को लेकर मै सरकार से यह कहना चाहूगा —किराये की रसीद देनी चाहिये ऐसा कमीशन ने कहा है — लेकिन चव्हाण साहब जानते हैं—बम्बई जैसे शहर में सब-लेटिंग सब-सब-लेटिंग में लोग रहते हैं—कौन रसीद देता है । क्या मालिक कोई रसीद देता है? क्या टेनट कोई रसीद देगा? रसीद की जो शर्त लगाई गई है इस से छोटे कर्मचारियों के लिये बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी । एक तरफ आप स्वय उन को क्वार्टर नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ आप उन पर रसीद की शर्तें लगाते है—इस का नतीजा क्या होगा । इस के ऊपर उपाध्यक्ष महोदय आप स्वंय सोचिये ।

पेन्शनरों के साथ कमीशन ने न्याय नही किया । मैंने पहले भी चव्हाण साहब को सूचना दी थी—पब्लिक सैक्टर मे जैनरल इन्शोरेंस में एक आदमी के साथ पैशंन का जो करार हुआ है उस मे 18 साल के पहले यदि उस की "अकाल मृत्यु" हुई तो उन के बच्चों को 18 साल तक पेन्शन का करार पब्लिक सैक्टर मे जैनरल इन्शोरेश आपने अपने हाथ मे लेने के बाद किया । उस पत्र का आपने जवाब भी नही दिया—शायद जाच कर रहे है कितने दिन लगेंगे, पता नही . . . . . .

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) . सही जाच करनी पड़गी ।

श्री मधु लिमये : ठीक है जरूर कीजिये ।

अन्त मे मैं एक बात कहना चाहता हूं—इस सरकार मे थोड़ी भी सच्चाई होती तो वह प्रगतिशील वेतन कमीशन गठित करती, वेतन श्रेणियों के बीच की दरार को पाटती और निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक धन्धों में

[श्री मधु लिमये]

भी इसी नीति को लागू करती । इसी सम्बंध में दो प्रोफेसरों ने अपने नोट-आफ-डिसेंट में क्या कहा है ? जब चौथे वर्ग के न्यूनयम वेतन की बात आती है तो सरकार कहती है कि खेतीहर मजदूरों को कितना वेतन मिलता है, असंगठित मजदूरों को कितना वेतन मिलता है लेकिन अफसरों का वेतन तय करते समय खेतीहर मजदूरों और असंगठित मजदूरों की याद नही आती है । उन्होंने कहा था—

> "The maximum pay under the Central Government with 1960 as base year was 117 times as high as the per capita income and 37 times as high as the minimum pay."

ये वेतन उन दो प्रोफेसरों ने कही थी । यह तर्क सेगत है सब के लिये या देवा खलासियो के लिए, फिटरों के लिए फायरमैन के लिए है। खेतीहर मजदूरों की हालत हम भी जानते है, उन की हालत वास्तव में बहुत खराब है, लेकिन कुछ तो सामाजिक न्याय की भावना सरकार की वेतन नीति मे होनी चाहिये ।

यह बहुत बढ़िया मौका था—यदि सरकार अधिकतम वेतन 1850 रु० कर दे और न्यून्तम वेतन 185 रुपये कर दे और तब सुझाव ले कर आये कि हम ने बड़े लोगों का वेतन भी घटा दिया है, अब उन की जो रेशों हैं तो हम लोग अवश्यसोचेगे । जो अंन्तर है, वह 1:10 का रह गया है ।

अमेरिका पूजीवादी है, अमरीका में रेशो है 8 : 7 और यहा समाजवाद, गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ की बात की जाती है तो अंतर है 3 : 7 गुना 110 का ही रेशो रखिये । ट्रेड यूनियन वाले नही मानेंगे तो कम से कम मेरे जैसे लोग कहेंगे कि यह ठीक है । साथ ही दाम घटाकर दाम बांधने की निति को अपनाओ, दामों को स्थिर करो, जो बड़े लोगों के वेतन भत्ते है उनको घटाओ, 1 और 10 में सारे वेतनों को ले आओ पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर में भी उसको लागू करो और एक पूरी राष्ट्रीय वेतन नीति अपनाओ । यह हो जायेगा तो मे मानूंगा कि समाजवाद की दिशा मे अपने कोई एक कदम आगे बढ़ाया है ।

SHRI A. P. SHARMA (Buxar): First of all, I would like to say that the very approach of the Pay Commission in evolving the pay scales of various classes of employees was not only not realistic but was far from satisfactory. When we appeared before the Commission, we pointed out to them that the Third Pay Commission was necessitated because two successive Pay Commissions, the First and Second, could not do justice to the employees in this country. At that time, the Commission retorted that after their recommendations were out, they were quite sure that we would come out with the same grievance, namely, that the recommendations of the Third Pay Commission are not satisfactory. Now we find after the publication of the Report that in certain respects of the benefits and emoluments of employees, the position has deteriorated. They have made certain retrograde recommendations.

When questions were asked the other day in the House by Shri S. M. Banerjee, what I said at that time and I would repeat today also that in the trade union movement or the negotiations between the employees and the management, no employees' organisation could compromise for a reduction in the present emoluments or in the favourable service conditions of the workers. As a matter of fact, the first and foremost duty of the labour and trade union movement is to safeguard the existing

interests, the existing emoluments and to create new rights and privileges to improve the service conditions of the workers.

Here in this Report, we find that almost the same mistakes have been committed, as it were, by the First and Second Commissions. The approach of the Commission was also defective in evolving the salary and pay scales of the employees because it has taken 1969 as the base without considering what has happened between 1969 and 1973. Everybody known that during this period, there has been a steep price rise in most of the essential commodities. but they have been compensated here and there by some *ad hoc* increment in the form of DA. We would have been very happy if the Commission, while formulating their recommendations, had taken all these things into account. Unfortunately, they have not done so. That is why whatever expectations the workers had from the Pay Commission have been belied.

In this respect I should like to appeal to my friends who are interested in the well-being of the workers that they should treat this question purely as an economic question. This issue should not be treated as a political issue. Unfortunately we find that in most of these things politics has become the uppermost interest and the interest of the employees has been given secondary importance. My approach to the recommendations of the Pay Commission will be purely economic and I should not like to indulge in politics. Therefore in the beginning I should request my friends, especially Mr. Jyotirmoy Bosu, not to indulge in politics so far as the salaries and conditions of service of the workers are concerned.

At the short time at our disposal it is not possible to deal with most of the recommendations and hence I shall deal with certain major recommendations which affect the generality of workers in this country. The first thing is the minimum wage. When the Pay Commission was appointed, this question was not before it; it was at our instance, not at the instance of politicians like Mr. Madhu Limaye, that Government was forced to change the terms of reference and this matter was referred to the Pay Commission...(*Interruptions*). Based on the recommendations of the 15th Indian Labour Conference, the Pay Commission arrived at a figure of Rs. 314 as the minimum. I want to make it clear that this is a calculation of the Pay Commission, not a recommendation. We have discussed this question, we meaning trade unionists, not politicians like Mr. Madhu Limaye; my friend Shri S. M. Banerjee was present. Whereas the Pay Commission has itself worked out a figure of Rs. 314 as the minimum wage, they have for some reason come out with a formula—whether it is convincing or not, I am not going to argue now—that for a vegetarian,—what Mr. Madhu Limaye calls *ghas,* he has used that term *ghas,* but in my opinion *ghas* is not vegetarian, —the minimum should be Rs. 196. They have worked out a vegetarian and non-vegetarian formula. I do not know why in their wisdom later on they have come to the conclusion that the minimum wage should be fixed at Rs. 185/-. They came to the conslusion that the minimum should be Rs. 185. There had been a thorough discussion amongst the trade unionists on this. We had an opportunity to discuss this question with the Government also. We have made it clear that between the minimum of Rs. 185 recommended by the Pay Commission—of course, it is a majority recommendation—and their calculation of Rs. 314 as per the recommendation of the 15th Indian Labour Conference, there should be some way out to find some compromise. We also feel that although the Pay Commission may have calculated Rs. 314, I am quite sure none of our friends on the other side of the House can suggest today that Government will be in a position to pay Rs. 314. Here comes politics and not economic consideration. I am not arguing that Rs. 314 should not be given. The difference between their feeling and our feeling is that they feel something inside the House and something else outside. But whatever we feel, we feel one and the same everywhere and we are prepared to speak out our minds accordingly.

[Shri A. P. Sharma]

As I was saying, there should be some way out to work the minimum wage of the workers. I do not think the recommendation of the Pay Commission of Rs. 185 as minimum wage will be acceptable to anybody. That has been made quite clear to the Government.

On the question of dearness allowance, we have had various commissions from time to time like the S. K. Das Commission, Gajendragadkar Commission and now the Third Pay Commission. I do not know whether the Pay Commission's recommendation in this regard can be acceptable by any standard, because it appears they have not considered this question very seriously. If you look at the price index, only in May and June, there has been an increase of 9 points. Every time we had gone before the Government for an increase in D.A. there had been a case for increasing it. Whether it was given in the form of interim relief or *ad hoc* relief, the workers have proved that there is a case for increasing the D.A.

Therefore, again to recommend that the workers will have to wait for one year for working out the average increase in the cost of living index to earn dearness allowance at a particular point looks very ridiculous. They should have taken into account how the prices are rising so quickly in such a short time. Therefore, while I would not like to suggest like Shri Madhu Limaye that the moon should be brought from the sky, I would say that the dearness allowance should be payable to the employees for every increase of five points over a period of six months. This is one of the recommendations of the S. K. Das Commission and I am sure the Government will take this into account.

Coming to pay fixation, if we look at the formula prescribed by the Pay Commission, we will find that employees with longer service will sometimes draw lesser salary than the employees with shorter service. So, we have suggested that point to point fixation should be the criterion for fixation of pay. If that is not possible, the seniority of service of the employee must be reflected while fixing the pay in the new scales.

Coming to the date of implementation of these recommendations, whenever this question came up before the House, my hon friend, Shri S. M. Banerjee, said that the Pay Commission wanted to prolong its work because the members of the Commission wanted to continue in their jobs. Of course, I did not agree with him there. The Commission was expected to submit its report by the 31st December 1972. This period was extended by another three months. Now the Pay Commission says that the recommendations should be effective from 1st April, which is very unfair. I did not expect that the Commission will make such a recommendation. We have already pleaded before the Government that the recommendations of the Pay Commission should be given retrospective effect from the first day on which the Government servants got *ad hoc* interim relief.

Then come to the retirement benefit. If you look at the recommendations of the Pay Commission on this point, they are retrograde recommendations. They are not any improvement over the recommendations of the Second Pay Commission. For want of time I cannot go into the details. While considering the retirement and pensionary benefits of the employees, I hope Government will see to it that the conditions of service of the employees are not adversely affected.

Then I come to the bonus, which is a very burning issue. I would not like to say much on this.

Sometimes, the Labour Minister in this House said that the bonus is not a serious issue before the Central Government employees. I am talking of specially about those Central Government employees who are governed under the Industrial Disputes Act. There is absolutely no confusion in my mind. Sometimes, they say that bonus is a deferred payment and,

therefore, perhaps, there is difficulty in making the payment. But I want to ask at this point of time from the Government as to whether the Government is prepared to consider this question. We must know that.

15 hrs.

I quite remember, our friend Mr. Khadilkar, saying in this very House that this question of payment of minimum bonus to the industrial employees of the Central Government will be considered after the recommendations of the Pay Commission were received. This is a specific statement he has made although, I must say, the Pay Commission has nothing to do with the payment of bonus to the Central Government employees. In any case, this is the commitment of the Government and, I hope, while taking their decision on the implementation of the recommendations of the Pay Commission, the question of bonus will also be considered by the Government.

Lastly, there has been a big controversy going on in this country about one thing. Of course, we have seen through the newspapers up till now and the Government has not expressed their views officially about it. We raised this question in the last meeting of the Joint Consultative Machinery. We have not come to know about the official view of the Government that, if there is any change made to bring about any improvement in any of the recommendations of the Pay Commission, it will automatically become a subject-matter of arbitration and, therefore, it is difficult for the Government to make any change even for improving some of the recommendations of the Pay Commission.

Here, I would like to appeal to the Finance Minister and the Government that if he looks at clause 20, sub-section (2) of the Rules and Procedures of the Joint Consultative Committee, it clearly says:

"Matters determined by the Government in accordance with the recommendations of the Commission will not be a subject of arbitration for a period of five years."

It is written very clearly that it will not be a subject-matter of arbitration. But they say that if they make any change, then it becomes a subject-matter of arbitration. Ultimately, whatever changes are made, whatever decisions are taken, they are all subject to the approval of Parliament. If there is any difficulty, they can place those cases before the Parliament.

Before I close, I would like to emphasize that if any clause of the JCM stands in our way or if the whole JCM stands in our way in bringing about a satisfactory settlement about the problems of workers, either that clause should be changed or suspended or the whole machinery should be scrapped. This JCM is not meant for creating an obstruction in solving the problems of workers. It is to help in solving the problems of workers. Therefore, no legal position should be taken by the Government in this respect. I would request the Finance Minister to kindly look into this aspect of the matter and see that the door for negotiation, for settling the problems of the workers, should not be closed. This has been the opinion of all the trade unions. As soon as the Report of the Pay Commission was published, I find that almost all the trade unions requested the Government to open up negotiations regarding the implementation of the recommendations of the Pay Commission.

With these words, I conclude and I once again appeal to my other friends that this should be treated as an economic problem and that it should be solved in that manner instead of making it a political issue.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I can humbly appeal to my hon friend, Shri A. P. Sharma, as he pleaded that it is not a question of politics that should be brought in here, and we say that it is hundred per cent politics. As soon as the Pay Commission's Report came out,

[Shri Dinen Bhattacharyya]

throughout the country, there have been protests after protests in all Departments, in all sections, of the Central Government. It has belied the hopes and expectations of the Central Government employees. Now-a-days, you are discussing the "Approach to the Fifth Plan". What should be the wage structure. That is also discussed there. And this Pay Commission's Report will be used as a handle by the Central Government, in fact, to freeze the wages. That is the main point. Mr. Sharma is dealing with railway-men. He has not yet learnt any lessons from the strike of the loco running staff. They tried to betray the workers, they opposed it tooth and nail and Government started to crush the movement by its own military and police and sending the leaders to the jail...

SHRI A. P. SHARMA: You are hundred per cent wrong. We never opposed it and we will not oppose it.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: You had opposed it.

I say, the question of politics must be brought in. What has the Pay Commission done? Like the Pandora's box, as soon as this report was lifted by Mr. Chavan, the whole country was surcharged with the angry protest by Central Govt. employees the whole country came to know what was the shape of things to come. After implementation it will be the basis for the next five years regarding fixation of wages, dearness allowance, etc.

Coming to the wage fixation, what was the demand of the workers, the employees all over the country? It was a need-based minimum wage. Government, on its own, did not fix the formula of need based minimum. It was in the year 1957, after series of struggles by the workers, including government employees, that the 15th Indian Labour Conference adopted the principle of need-based minimum wage, and a formula was evolved. This was the demand of the Central Government employees to the Pay Commission and it has denied this demand of the Central Government employees. Even at the outset, when the Commission was set up, in the terms of reference, this was not there that this should be the basis. Only after there was the threat of strike by the employees, this formula was taken for consideration by the Commission in its terms of reference. Now what have they done? They have calculated on the basis of vegetarian diet. As Mr. Madhu Limaye said, the employees are supposed to take only grass and not meat or egg which is meant for the higher echelons and not for ordinary clerks, ordinary employees. Even on that basis, the Commission's calculation or estimate was—and even Mr. Sharma has admitted that—to the extent of Rs. 314, but while giving its award or recommendation, it slashed it down to Rs. 185. It is all *tikram;* I do not know what is the English term for *tikram*...

AN HON. MEMBER: Trickery.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Yes; trickery.

A new entrant to government service is supposed to be a bachelor. Only after five years he will be entitled to Rs. 196/-. So, for five years, he cannot have wife and children. While calculating, the basis taken was not the formula evolved in the 15th Indian Labour Conference. There, three consumption units were taken excluding the earner; here, the earner has been included within that three consumption units. Just see the fun. So, ultimately, this is nothing but a trickery and cheating the whole people because not only the 20 or 30 lakhs of Central Government employees but also the State Government employees, other employees of the Municipalities, the Zila Parishads, etc. have also been expecting some change on the basis of the Pay Commission's recommendations. But this Pay Commission ultimately produced a hoax for the Central Government employees and I will say that there is politics behind it and that politics was enunciated by Shrimati Indira Gandhi as well. In many meetings she has said—she was very loud—to the rural folk, 'You village folk, I cannot do anything

for you because the Government employees and other workers are eating up everything'. What is this politics? We know. She is shielding her own policy to encourage the black-marketeers, big monopolists, landlords and the high officials who are responsible for pauperisation and deteriorating conditions of the rural poor and other down-trodden people ... (*Interruptions*) and only to pit the rural and unorganised people of urban area against the organized workers of the towns including the Government employees that Shrimati Gandhi uttered all this. What has the Pay Commission said? According to them (Pay Commission):

> "There is much to be said for the view that if additional funds should be made available to the Centrad Government by various economy measures or by additional taxation and economy in non-Plan expenditure, this should first be used for ameliorating the lot of the people who are unemployed or under-employed rather than ensuring a minimum wage related to certain norms as set by the 15th Labour Conference for a section of the community".

Further, it said:

> "Having regard to the prevailing level of wages in the agricultural sector and the general minimum level in the trade and industry, the adoption of the minimum recommendation based on the 15th Indian Labour Conference norms at this stage would be tantamount to misdirection of resources."

What does it mean? Just to the rural poor you are saying this. What did they do all these years? The last Pay Commission was set up ten years ago. After ten years another Pay Commission has come. What is the condition and the rate of pauperisation in the rural areas? Why is the pauperisation going on like anything all over the country, not only in the rural areas but also in the urban areas? What have you done during this time? Please do not give stunts, please do not create further illusions, please do not try to fool the people in this way who are in the same way exploited by the policies of the Government as well as by the big monopolists, landlords and their stooges. A comparison has been given by Mr. Madhu Limaye. He has ably put it. What have you done? The Pay Commission says that they have not increased the emoluments of the Class I employees most of whom belong to IAS. But it is known that in 1965 when there was Indo-Pak war and the Prime Minister was going round and the Government was going round that everbody must sacrifice, what did these IAS officials do? They got an increment to the extent of Rs. 500 even.

Now you say that you are narrowing down the gap between the lowest paid and the highest paid, between the top and lowest paid workers. This is the way you are doing it! You are keeping the gap 1—20 as it is, whereas the demand by all concerned is that it should be 1—10. When the Commission was set up—the Secretary and the IAS people are clever—they did not allow any such men to be included in the Commission who may go against their interest. That is why I say, it is 100 per cent officer-biased and pro-monopolist and fully reflected the policy of the Govt. This Commission is nothing but that.

In all departments the slogan or the demand raised is that JCM only will not do; decide on the basis of the principle of the need-based minimum, settle it on a bilateral basis with all the unions including the Railwaymen's union. This is the demand. But they will not do it. I know it. They will impose their will upon the employees. They will have to face the consequences. Beginning from the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi and her govt. including Mr. Chavan, they are fully responsible for the consequence of anti-employee findings of the pay commission.

AN HON. MEMBER: You are threatening.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: No question of threatening. They are responsible. You have seen it in the

[Shri Dinen Bhattacharyya]

case of the locomen's strike. My next point is this. This is about neutralisation upto 100 per cent. There was also the demand for point-to-point fixation of D.A. What we find is that the real earning of the employees has already been seriously eroded. Further erosion will be there if this formula of DA suggested by the Commission is accepted *in toto*. This is my submission.

What happened after the First Pay Commission's Report? After the First Pay Commission's Report the pay was fixed at 30 and dearness allowance was fixed at 25 bringing it up to a total of 55. Now 185 is fixed. And, what does this mean? In the meantime the value of the money has gone down. If you calculate on the basis of the existing value of the money, which is now standing at the rate of 25 paise per rupee, what do you find? This figure of 55, if you calculate in proper way, would come to 186 and your Commission has fixed it at 185—that is to say, one rupee erosion. If you go up what happens? This erosion goes up still further and further. In the case of those who were getting Rs. 60 total in the year 1947 what happens to them. They will get Rs. 191, which, actually if you calculate properly on the cost of living index basis, comes to Rs. 203, that is to say, Rs. 12 erosion Can anybody deny this? You are cheating them in this way. The total money accumulated by this method of erosion, the total money cheated by the Central Government, if I may put it that way, would amount to more than Rs. 4,000 crores. (An hon. Member: Strange). So, this will again go up and this will again continue in the case of fixation of the dearness allowance. So, what we demand is that there should be 100 per cent neutralisation and point to point fixation of dearness allowance.

SHRI A. P. SHARMA: What is your suggestion regarding D.A.?

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: I say that there should be cent percent neutralisation and the faulty method of calculation must be changed. If the rice for example sells at Rs. 7 a kilo, the compilation of the price index by the Government will indicate that it is sold at Rs. 1.50 a kilo. It is not done by the Central Government alone. This is the method adopted everywhere. That is why throughout the country there is a demand for the change in the method of calculation which is totally faulty. This is the way of cheating the workers from the real increase that they should get in D.A. whenever there is an increase in the price index. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bhattacharyya has taken 16 minutes instead of nine. Please do not provoke him because he takes more time that way.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA. I now come to the issue of fixation of pay. The employees have been agitating over this. An employee who has been working for fifteen years in the scale of 170—185 will be getting only Rs. 196/- no doubt. That is after 15 years of service, he is getting that. You are giving Rs. 185 in the case of a new entrant and after five years; he may get Rs. 196/-. In the case of an old entrant he gets the same Rs. 196/- after fifteen-twenty years. This way the employees are agitating.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now you will please cooperate. Please listen to me. The House has fixed four hours.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): That is his principal business.

MR. DEPUTY-SPEAKER. Let me finish. I am stating the fact—I am not giving a judgment or a decision—that the House has decided to give four hours for this. Even so, having regard to the importance and the volume of the report. I have gone out of my way. For example, Mr. Bhattacharyya, according to this timing, should take only 9 minutes. On the basis of these four hours, you should take 9 minutes whereas you have taken about 16 minutes or so, almost double the time. There should be a limit somewhere. You can take another five minutes. But, please conclude.

SHRI S. M. BANERJEE: Then, the time should be extended.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That means extension.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Now I come to the main thing. Sir, the Pay Commission was set up on 23rd January, 1970. You are giving effect to the recommendations from 1st March, 1973 only. That means the people who will retire after this date will only get the retirement benefit. But, those who retired before 1969 or in between 1969 and 1973 March, they will get nothing. You have to concede to the demands of thousands of pensioners with regard to the rise in prices. They too are suffering on account of the rise in prices. But, they will get nothing from the Pay Commission's report. This point must be taken into consideration. Here too they make a discrimination. In the case of top people, they raised the minimum pension amount to Rs. 1,000/- but for the so called ordinary people, it is only marginal. Why is this discrimination in regard to fixation of minimum incremental scale and retirement benefit? I do not know what Shri Chavan will reply to this. Then, Shri Madhu Limaye mentioned about allowance to the nurses. I do not want to repeat it. But, I would like Shri Chavan to note why the Pay Commission has stopped the messing allowance of Rs. 60/- to nurses.

What is the justification? Is there any? They were getting this amount. You know the working conditions of the nurses. In fixing their pay scales, you have discriminated as compared with the other Central Government employees. Over and above that, they have curtailed existing benefits.

Coming to the doctors, engineers, scientists etc. it is a fantastic thing that is happening. Nowhere else in the world you will see this. It is only in India that this happens because of the legacy of the British. They have taught you all. From the Minister to the Secretary, you have learnt this bureaucration from the Britishers and for which the high echelons have been kept in a very grandiose condition. Doctors, engineers and other scientists and technicians have been deprived of both status and other facilities enjoyed by I.A.S. and they have been asked to work under IAS officers who may be a good administrators regarding the law and order question, but these IAS people know nothing in regard to specialised jobs like doctors, technicians etc. We saw in the Delhi Electric Supply Undertaking. What has happened there? He, who is an I.A.S. had to leave the post because the technicians raised their voice against the discriminatory attitude against the technicians and other officers.

Then Shri Limaye had mentioned—and I repeat...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why repeat?

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: As regards the ITOs, there are two grades, Grade I and Grade II. Why? Grade II people are given a most responsible job, the same job, without the benefit of the service conditions of Grade I. Why not make it one? You are socialist. You are samajwadis. Is this samajwad? Grade I will go by air and Grade II by train which may be derailed on the way. Same work, same pay—this principle has not been adopted. This should be seriously considered.

There are other cases of discrimination. The pay scales of the staff of the office of the Comptroller and Auditor General should be separately dealt with. They have not been given the pay scale given to the Secretariat people. Why this discrimination? Secondly, as per the Constitution, their pay scale should be separately dealt with in consultation with the Auditor General. That has not been done in this case. There is discrimination also in regard to nurses, doctors and scientists, in the Income-tax Department, everywhere.

[Shri Dinen Bhattacharyya]

You will take exception to it if I mention about the Lok Sabha Secretariat. I will not mention anything. But when I was a member of this House from 1962 to 1967, there was a Committee. Perhaps you may remember that when Sardar Hukam Singh was Speaker, at that time there was a Committee. There is no scope for representation by the Lok Sabha Secretariat staff and employees anywhere. They have to go by the pro per channel. Elsewhere there are unions, there are negotiating machineries. Here there is nothing. So I demand that a pay body be appointed in which MPs might be included; if not, at least the Speaker and the Chairmen of the Public Accounts Committee, the Estimates Committee and the Public Undertakings Committee may form the Committee and some members of both Houses may also be included in it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Not the Deputy-Speaker? I propose that the Deputy-Speaker be included

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: In the railway department, you have deprived them. You have not given any benefits to them. Your Pay Commission has admitted that the railwaymen have not been given any increment. There is no change in the service conditions; no improvement in the case of 17 lakhs of workers even after 26 years. You have not done anything for the casual and the temporary workers. They are being denied even the minimum benefit that has been done to the others.

I come to the conclusion—bonus. Why could there be discrimination? You have said that bonus is deferred wage; further there is big gap between the real income and the income earned. Why do you not introduce bonus for all including the railway, post and telegraphs, defence?

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is a good point to conclude with.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: I appeal to Mr. Chavan's conscience. Are you satisfied with the Pay Commission's recommendations? You go over the whole country. Whatever Shri Sharma and his friends may say, nowhere in no department have the workers accepted it. So, Mr. Deputy-Speaker, please tell them to scrap it and negotiate a settlement on the basis of the accepted principle of the need-based minimum wage and 100 per cent neutralisation, and no discrimination anywhere, and equal pay for equal work. You have spent nearly Rs. 70 lakhs of public money. I demand that it should be scrapped. The recommendations will further aggravate the situation and bring discontent in the country. Scrap it and do the needful; that is all I can say.

MR. DEPUTY-SPEAKER: To maintain the balance of the debate, I shall call two Members from the Congress Party and one from the Opposition... (An Hon. Member: Why?) I have given the reason... (*Interruptions*) I do not understand this. Order, please. I have a request from the Minister of Parliamentary Affairs that the list from the Congress Party being very long. Members should not take more than ten minutes each.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You stand to oppose everything; even when I am regulating and allotting the time. Have you become their spokesman also? If Mr. Banerjee is their spokesman, I shall hear him.

SHRI S M. BANERJEE: The first four speakers always get time to their heart's content and restriction comes later on... (*Interruptions*)

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने इस सत्र का सब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज राष्ट्र के चिन्तन को चुनौती है। राष्ट्र की नियोजन विधि के सामने एक प्रश्न है

उस प्रश्न के उत्तर की खोज में मैं वेतन आयोग की सिफारिशों के बल उस की कमियों या उस की व्याख्याओं में नहीं जाऊंगा। समय के अभाव के कारण केवल सिद्धान्त की बातें ही सदन के सामने रखूंगा।

सब से बड़ा प्रश्न यह है कि कर्मचारियों को जो वेतन मिले उस का आधार आवश्यकता हो या न हो? बुद्धिजीवियों के बीच में बहुत से लोग लोग मिलते हैं—विशेषकर अधिकारियों के बीच में—जो कहते हैं कि किस आधार पर आवश्यकताएं तय हों? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है—जब अंग्रेजों की सरकार शुरू हुई थी, कम से कम मेरे प्रदेश—उत्तर प्रदेश में—तो कानून-गो और पटवारियों की तनख्वाहों का जो आधार रखा था—यह 1870 की पुरानी बात है—उसका आधार आवश्यकता थी। पुरानी बात है—सन 1878 और 1888 में, जब आर्डिनेन्स कमीशन और आर्मी कमीशन बैठा, पहली बार डिफेन्स वर्कर्स के वेजेज को जांच हुई, । तो इन्होंने भी यद्यपि दूसरे ढंग से आवश्यकता पर आधारित वेतन के प्रश्नों को उठाया। यही नहीं हमारे महापूजनीय, कांग्रेस के जन्मदाताओं में से एक, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष—श्री दादाभाई नारोजी ने 1888 में जब सरकारी कर्मचारियों की ओर से अंग्रेज सरकार को इंगलैंड में वेतन वृद्धि हेतु जो प्रतिवेदन दिया, वह प्रतिवेदन उन्होंने भी "नीड-बेस्ड-वेज" की मांग की थी। उस में उनकी पुस्तक—पावर्टी एण्ड ब्रिटिश रूल इन इण्डिया—जो 1901 में प्रकाशित हुई उसमें संग्रहित है।

15.36 hrs.

[SHRI S. A. KADER *in the Chair*]

उस समय बात क्या थी? उस समय डा० बरिज नहीं थे, डा० एकरायड नहीं थे, उस समय दादाभाई के सामने केवल सर्जन जैनरल पैट्रिज द्वारा बनायी हुई खाने की एक सूची थी जो प्रवासी भारतीयों को पानी के जहाज में मिलता था।

यही नहीं, इस के बाद 1920 की जनवरी की बात है—उपाध्यक्ष महोदय—मुझे थोड़ी देर के लिए उस मैन्ड्रन असेम्बली को इस पार्लियामेंट का पूर्व-रूप मानने की आज्ञा दें—तो कहूंगा कि इस पार्लियामेंट के सामने पूर्व जन्म में श्री विट्ठल भाई पटेल और श्री खापरडे ने एक कटौती का प्रस्ताव रखा था, जिस में लाखों रुपये में से केवल, दो रुपये की कटौती का प्रश्न था, उस प्रश्न को लेकर पोस्टमैनों की वेतन वृद्धि के लिये एक कमेटी बनाने की मांग थी जो इस पेकमीशन के माता या पिता थी।

यही नहीं—अहमदाबाद के अन्दर जब टैक्सटाइ मजदूरों की हड़ताल हुई तो गांधी जी ने जो समझौता किया, उसमें उन्होंने लाला शंकरलाल बैंकर को नियुक्त किया कि वह मजदूरों का जो खर्चा अहमदाबाद में होता है, उस की जांच करें। उन्होंने कैलोरीज के बल पर फैसला नहीं किया, उस समय गांधी जी और वल्लभ भाई आर्बिट्रेशन में मजदूरों के प्रतिनिधि थे और ध्रुव साहब उस के अध्यक्ष थे, उन सब लोगों ने मजदूर जो व्यय करता है, उस को आवश्यकता मान कर वहां पर बात की।

उस के बाद बिहार प्रदेश में राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी—यह बात 1939–40 की है—डा० राधाकमल

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

भी उस के सदस्य थे, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी मे अर्थ-शास्त्र के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी नीड-बेस्ड-वेजेज की ही चर्चा की। उस के बाद 1957 की बात है—जो लोग बार-बार कहते है कि ये बाते पुरानी पड गई है—मैं माननीय सदस्यो से यही कहना चाहता हूं—कि चाहे आप डा० एकरायड की डायट को माने या जो बाद मे डाक्टरो की कमेटी बनी, उस मे जो संशोधन किए उस को माने, चाहे उस के पहले पारीज की बात को माने और चाहे डा० राजेन्द्र प्रसाद समिति द्वारा कही गई बात को माने या सर्जन जैनरल ने जो सूची बनाई थी उस को माने—प्रश्न यह है कि यह सिद्धान्त इस सदन को तय करना ही पडेगा, कि वेतन का आधार आवश्यकता हो, फिर तो किसी वक्त बैठ कर इस को तय किया जा सकता है। लेकिन अभी तक यह बात तय नही हुई है। हम तरह तरह के मतो मे उलझे हुए है, लेकिन अब यह बुद्धिजीवियों के लिए चुनौती है कि रुपया देने को नही है तो क्या बुद्धि भी देने को नही है। इस लिए कम से कम उन से इस बुद्धि की आशा तो है ही। वे हम को रास्ता बतलाये—जितने मत-मतान्तर है उन का समाधान कर आवश्यकता के अनुसार वेतन का निर्णय कैसे हो सकेगा—मै इस बात को यही पर छोडता हू। आप लोगो के सोचने के लिए।

रह गई बात महगाई भत्ते की। महगाई भत्ता कर्मचारियो के लिए कोई दया की भीख नही है। जो मोटर रखेगा, वह उसकी रिपेअर के दाम भी देगा। जो वेतन तय होते हैं, उस मे बढती हुई आरोहण की ओर अभिमुख महंगाई से जो चोट पहुचती है, जो क्षरण होता है, यह उस क्षरण की पूर्ति के लिए प्रयास मात्र है। यह डेमरैजेज को होने वाले डैमेज की एक रिपेअर मात्र है, तो फिर उस में शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति की बात क्यो न हो—यह भी एक प्रश्न है एक चिन्ता की बात है। इस विज्ञान के युग मे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर के इस प्रश्न का समाधान ढूंढ न सकें तो यह चुनौती राष्ट्र के लिए है, इस मे किसी तरह से मुख मोडा नही जा सकता।

रह गई बात यह—कि जहा तक पै-कमीशन की सिफारिशो का सवाल है, मुझे मतभेद तो बहुत है। लेकिन यदि मै कुछ प्रश्न करू तो यह कहा जा सकता है कि कोई भी कमीशन अपने सामने प्रस्तुत साक्षियो और प्रतिवेदन मे दिये गये आकडों के आधार पर ही निर्णय करता है। मैं तो उन लोगो मे भी था जो कमीशन के सामने गये थे। लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है—कि बात तो एक है—पहले पै-कमीशन से लेकर आज तक जब जब कमीशन बने—1913 मे बने रायल कमीशन—जिस के लार्ड इस्लिंगटन चेयरमैन थे—जिसके आधार पर अंग्रेजो के युग मे वेतन तय होते आये थे, उसके सिद्धान्तों को तिरस्कार हुआ। कि इस्लिंगटन कमीशन के द्वारा निर्धारित सिद्धान्त ठीक नही हैं, उनको तिलाजलि दे देनी चाहिए यह कह कर यदि वे कमीशन नये सिद्धान्तो का निर्माण न कर सके तो उस वेतन आयोग की सिफारिशो को तो हम केवल तर्क के ही आधार पर जांच सकते है और उनकी परीक्षा कर सकते है। जब हमारे सामने वह कोई सिद्धान्त न हो और समाजवाद की बात आ जाये, सोशल जस्टिस की बात आ जाये तो हम कैसे कहे कि वह तर्कसंगत है।

जहां तक डिफेन्स वर्कर्स की बात है, इंडियन नेशनल डिफेन्स वर्कर्स की बात सामने आती है, हम रुपये आने पाई की बात नहीं करते कि किस ग्रेड में क्या मिलेगा लेकिन यह प्रश्न तो अवश्य है कि आवश्यकताओं का सृजन कैसे होता है, वस्तुओं की उस टोकरी में जो आवश्यकता की पूर्ति करती है, क्या क्या चीजे है इस सदन को यह सब सोचना पड़ेगा और यह भी सोचना पड़ेगा कि आवश्यकता का जो भी आधार हो उसमे यह जो डीयरनेस एलाउन्स है वह कोई चैरिटी की बात नही है, वेतन के पैकेट को होने वाली चोट की क्षति-पूर्ति शत्प्रतिशत् हो। बाकी चीजे लोग कह चुके है।

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): Mr. Chairman, I am rather surprised that such an important report as that of the Pay Commission should have been the subject matter of discussion only under rule 193 of the Rules of Procedure because the Pay Commission in the present context should take a different form. But, as I see it, there is no departure in the present report from the earlier reports. In fact, this is an exact replica of the earlier reports. As a matter of fact, the Pay Commission today should function as an instrument of social change.

The Third Pay Commission consisted of five members out of which three were either themselves in the ICS or IAS or were interested in the administrative services. There were only two other members, namely, Prof. A. K. Das Gupta and Shri Nihar Ranjan Ray, who have given a strong note of dissent. So, it is very necessary that this report should be gone into very thoroughly.

It is a matter of regret that even 25 years after independence we have not been able to reduce the disparity between the highest and lowest salary. Today the ratio is 17:1. It should not under any circumstances exceed 10:1.

I find that this Report follows the same old beaten track. Some of the officials who enjoyed a privileged position under the British regime continue to enjoy those privileges even now. There is glaring disparity between the IAS and other all-India services. As a matter of fact, when the Indian Civil Service was the backbone of the British imperialism, the concept of administration was different. In those days the administrators were to carry out the orders of their masters. Today they have to carry out the will of the people.

We find that the people of this country, ignorant as they are and poor as they are, have displayed the highest political maturity and returned our party to power and thus given us a very good government. We want to honour our pledges to the people. If we go by the same beaten track and do not bring about a revolutionary change in our approach, attitude, thinking and behaviour, I do not think we will go very far in the way of progress towards socialism. I personally feel that this is a subject which needs to be gone into thoroughly. I hold nothing against IAS or ICS officers. I do not hold anything against anyone.

We all know that the brightest of the boys, for instance 30 per cent of First Divisioners, only go to IAS. 70 per cent are Second Divisioners and Third Divisioners. But 80 per cent of First Divisioners normally go to medicine and engineering. This has been very strongly supported by our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. While addressing a Convocation at Roorkee in November, 1967, this is what she had said:

> "It is odd that the greatest doctors and engineers in the country who would be rated as the leaders of the profession and who save lives or add permanent assets to the nation, can rarely hope to receive the pay or status of Secretaries of Ministries. The brightest of our young men and women

[Shri Kartik Oraon]

choose engineering and medicine. If they happen to go into Government, they are very soon overtaken by the general administrator. This must change and I am trying to change it. The administrative system must reflect an individual's contribution to human welfare and economic gain."

This is not all. We have also given our pledges to the people. The manifesto of the Congress Party says:

"The Congress invites the nation's scientists and technologists to give their best to accomplish these exciting tasks of momentous importance and assures them that it would be its constant endeavour not only to accord them positions of standing and responsibility but also to involve them intimately in the processes by which governmental decisions are taken and implemented."

It would, therefore, be seen that the Congress Party is already committed to make full use of our scientists and technologists by providing them with opportunities to participate at all decision making levels as equal partners with general administration.

Here is a service which I consider to be a special tribe service because it enjoys all facilities. Once they become IAS officers, they can become the head of the Health Department; they can become doctors; they can become engineers; they can become scientists. They can become anything. It looks as if it is an insult to human intelligence that we cannot make a distinction as to who at the present moment can deliver the goods, whether it is a scientist or a technologist or an administrative officer. I hold nothing against them. But they have got a limited scope of work. I do not see any reason why they should be given so much advantageous position so far as their pay-scales are concerned.

As a matter of fact, if there are IAS officers for administration, there should be all-India services for all branches, for scientists, technologists, etc. On the recommendations of the States Reorganisation Commission, in 1956, these three all-India Services, that is, the Indian Forest Service, the Indian Medical Health Service and the Indian Service of Engineers, were to be constituted. Out of these three services, only one service, that is, the Indian Forest Service, was constituted. The Pay Commission should have taken special care to see that the pay-scales are worked out in such a manner that they should be able to develop a team spirit amongst different Services. But today, if you go through the pay-scales, I do not know what has made it to do it in this way. That is why I say that the Pay Commission has not been impartial. It has been partial; it has been biased against certain Services and biased for certain Services.

I understand that this question of granting parity amongst the three existing All-India Services and the Central Engineering Service has been summarily rejected without assigning any reason, thus creating classes within the class of All-India Services. The glaring anomalies in the pay-structure of the I.F.S. *vis-a-vis* I.P.S, I.F.S. and CFS(I) as recommended by the Pay Commission are as follows. You can see for yourself...

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down? I have got many names and if members go on taking extra time, then very few people will have the chance to speak. The time is limited Therefore, I would request the members, as soon as the first bell is rung, they should try to finish their arguments; one extra minute will be allowed and if the Member continues, from the second extra minute, nothing will go on record. That is what I propose to do. I have to control the debate and see that many people get the chance to speak.

I would now request you, Mr. Kartik Oraon, to conclude your remarks.

SHRI KARTIK ORAON: I would like to quote these figures so that it will be clear for everybody what makes them that important. For instance, the junior

scale in IAS, IPS, IFS and Central Engineering Services (Class I) has been kept as Rs. 700—1300. They have recognised that all the services are equal, their requirements are the same. But the scale, when he becomes District Magistrate, is Rs. 1200—2000; when he becomes Superintendent of Police, it is Rs. 1100—1600; when he becomes DCF (DEO), it is Rs. 1100—1600; when he becomes Executive Engineer, it is Rs. 1100—1600. The selection grade in IAS is Rs. 2000—2250 and in IPS Rs. 1650—1800. And the super-time scale...

MR. CHAIRMAN: Now I am calling the next Member. Mr. S. M. Banerjee.

SHRI KARTIK ORAON: There is no selection grade for other officers, for IFS and Central Engineering Services (Class I). There is this disparity. I request the hon. Minister that he should create All India Services of all faculties—engineering, medical, science, agriculture, forest, police and others and there should be one uniform scale for all the Services.

MR. CHAIRMAN: Shri S M. Banerjee. Only nine minutes.

SHRI S M. BANERJEE: It is very unfair. If it is only nine minutes, then I am not going to speak.

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।.....

MR. CHAIRMAN: What is the point of order?

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था प्रश्न यह है कि छोटी सादरी सोना कांड पर इन्होंने 6 घंटे बर्बाद किये और पे कमीशन के लिए समय नहीं है। माननीय बनर्जी को कम से कम 25, 30 मिनट का समय देना चाहिये, यह फैडरेशन के अध्यक्ष हैं इसलिए इन को मौका मिलना चाहिए।

DR. RANEN SEN (Barasat): Mr. S. M. Banerjee is the only person who has been working day in and day out.. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have a list of so many members.

SHRI S. M. BANERJEE: The other parties have taken 45 minutes and 35 minutes each. Government employees will not misunderstand me if I do not speak..

MR. CHAIRMAN: You have got your time.

SHRI S. M. BANERJEE: The Third Pay Commission's report has resulted in creating discontentment among all sections of Central Government employees We expected better results from the Third Pay Commission because they had all the data available—of the First Pay Commission and the Das Commission or the Second Pay Commission Naturally it is not only the 28 lakhs of Central Government employees who are disappointed, dejected and frustrated, but it is also the three wings of the Armed Forces who are equally disappointed with the Pay Commission's recommendations.

One of the terms of reference was the need-based minimum wage. It is for the first time that a Pay Commission has quantified it as Rs. 314/-. Still they have said that they cannot recommend it to the Government because Government will not be able to give. What have they recommended? They have quantified the need-based minimum wage on the basis of the 15th Indian Labour Conference as Rs. 314 but have recommended only Rs. 185/- as the minimum salary. Even Rs. 196 recommended by one of the Members, Mr. Pillai, has not been supported by his colleagues on the ground that a worker when he is employed in a

[Shri S. M. Banerjee]

bachelor and after some time, as the years go on, becomes a father of two or three children and then only he should get Rs. 195. . .

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: And he should be a vegetarian.

16 hrs.

SHRI S. M. BANERJEE: Yes, he should be a vegetarian. That is the formulation of this Pay Commission.. All the organizations including Mr. A. P. Sharma's organization have rejected Rs. 185 unanimously without any kind of reservation. To the Government we have made it abundantly clear on 6th July when we met the hon. Finance Minister and his colleagues that this was not acceptable to anyone of us and we unanimously demanded implementation of Rs. 314. But if the Government say that they are not in a position to implement Rs. 314, I would like to know from the Minister what his suggestion is. There is no parity with the public undertakings. An ordinary worker who starts as an unskilled worker or peon in HSL whether in Bhilai or Rourkela or Durgapur or in the Head Office of HSI is getting to-day Rs. 272 as the minimum salary. In the Reserve Bank, the pay is Rs. 135 and Rs. 130 Dearness Allowance. I am not talking of house rent and the city allowance and other things. So total is Rs 265. In the nationalised Class A Banks—it is Rs. 116 pay and Rs. 111 Dearness Allowance—total Rs 227. In the petroleum industry it is Rs. 218 Pharmaceuticals—Rs. 55 pay and Rs 330 DA—total Rs. 385. So, you will kindly imagine when we had demanded a need-based minimum wage and if we had demanded parity with the public undertakings. I do not think any harm has been done and I would, therefore, request the hon. Minister to kindly explain to us whether he is prepared to accept Rs. 314 and if not, what are his suggestions and whether he is going to bring the Central Government employees at par with the employees in the different public undertakings like HSL and whether he is prepared to give them Rs. 272 or the minimum salary of the bank employees—Reserve Bank or the nationalised banks. I want a clear reply to that.

Then I come to the DA formula. My hon. friend also mentioned this. We want automatic linking up of DA with the rising cost of living. This Government has miserably failed even after 26 years of freedom to bring down the prices. Prices are going up. Even the Prime Minister in her speech yesterday and the President of India in his speech the day before have mentioned about the rising prices, about hoarding and black-marketing and so on. What is the remedy to it? Is it not a fact that the salaried employees to-day are the worst affected? They cannot live within their income. In all fairness there should be further protection in the wages and that can only be done by the automatic linking of DA with the rising cost of living I want this formula to be adopted by the Government. This has been adopted by the Rajasthan Government and the Punjab Government and even by the UP Government in the case of electricity workers I want this automatic linking of DA so that there is no further erosion in the wages and I also want cent per cent neutralisation.

16 hrs.

About fixation of salary, what is the Pay Commission's formula? 5 per cent—subject to a minimum of Rs 10 and a maximum of Rs. 50. Where Rs 50 will be given to the top man. Rs. 10 will go the lowest-paid man. What is the rate of increment? Class IV—it is Rs. 2, 3, 4, 5 and Rs. 6 at the most.

Regarding Class III category, it is only Rs. 6 to Rs. 20 in special cases. With Rs. 100. The ratio ranges between 3.3 per cent to 8 per cent. Is it socialism? Are we going towards socialism? This is regarding Class I employees. I have nothing against Class I employees. Can he deny today, that all the other officers like doctors, engineers, like geologists, and other services, are

working well? Are they working less? Can we forget about the railway employees who saved the country and the defence employees who saved the country? There is one other point about which references were also made by my hon. friends. When there was invasion on India by Pakistan and the country stood as one man in 1965, we were asked to save money. We gave donations; we gave gold; we gave ornaments. What about the IAS officers? During this period from 1st September 1965 the Secretary's pay was raised from Rs. 3,000 to Rs. 3500; Addl. Secretary's pay was raised from Rs. 2750 to 3,000. Joint Secretary's pay was raised from Rs. 2250 to Rs. 2750. This is the way they wanted to discharge more responsibility! They wanted more powers and more powers cannot be discharged unless and until they got more by way of salary. They wanted to have their pound of flesh. This was a time when the country was facing foreign invasion and this was a time when the P&T employees and the defence employees and other sections of Government employees did not even take their overtime allowance. But these IAS officers got huge salary increase in this period. I would urge upon the Minister, if the Government cannot do it now, let them say, they will accept 314, in principle but they will pay in 2 years or 3 years. Let them bring parity with the public undertakings. The minimum wage as in HSI that is Rs. 270, should be given now. Point to point fixation should be done, because in respect of the employees whose services are more, after 10 years, they will be getting less. We are not fighting only for those who are in the colleges etc. but we are fighting for those who have spent the major part of their life in Government service, who have worked hard, in peace and in war. So, I would request the hon. Minister to accept the point-to-point fixation formula, subject to minimum of Rs. 20 to Rs. 30. I hope this will be accepted by the Government.

Then, about the date of pensionary benefits. I wish to say this. I request the hon. Minister that he should sit with the representatives of the employees to discuss the various aspects of this question. Retirement benefits should be increased. A question was asked in this House and this was replied to, that retirement gratuity in case of Class I officers had been raised from Rs. 24,000 to Rs. 30,000. That is, Rs. 6,000 increase in the case of his death. But in the case of Class IV employee, he does not get anything more.

Take the case of a class IV employee. He has a wife and children. He must also have a lion's share in the matter of death-cum-retirement benefits. There is discrimination in this regard between a Class IV employee and a Class I employee. Sir, it is a shame and it is a sad commentary on our planning. We talk of socialism in these days. And so, I would request the hon. Minister to see that this disparity is done away with completely.

Now I come to discrimination between industrial and non-industrial employees. Even in the case of toilets there is discrimination in regard to the officer and the industrial staff. This is something unique. I don't think that discrimination should be there. Why such discriminations should be recommended at all by the Pay Commission? This should be done away with. I would request the hon. Finance Minister that when we are talking of socialism, this sort of discrimination as between an industrial worker and non-industrial worker must be done away with

Coming to the various concessions, I find that these have to be curtailed or are likely to be withdrawn. The Pay Commission has recommended the curtailment of the concessions in the matter of house rent allowance, city compensatory allowance and increased in the working hours and overtime and children's education allowance. I would request the Minister not to accept this. The Pay Commission has no business to take away the concessions. I can tell him that if these concessions are taken away, nobody will be able to stop the major strike in the country.

It has been argued by my hon. friends that the date of effect of the recommendations should be from 1st March, 1970. This was the date when the sum of Rs. 15 to 45 was sanctioned as interim relief—not D. A.—because the Commission was to take more time and so, they wanted to pay some interim relief to the employees. We took this, as an advance? Advance against what? Advance against final submission of the report—final recommendations of the Pay Commission. The date of effect should be from 1st March, 1970. The demand is very legitimate. And I would request the hon. Minister to see that the employees who are retiring in good faith earlier than this should also be given the benefits. Suppose an employee had retired on 31st March, 1973. He is not entitled to any benefit because the Pay Commission has recommended the implementation of their recommendation from 1st April, 1973. Sir, I am getting numerous letters and I hope that the hon. Minister for Finance too must be getting more such letters. It is a gravast injustice done to those who have retired in good faith. After all, the Pay Commission should be generous enough not to deprive such employees of this benefit which accrues to them. Look at the conditions of the pensioners in our country. It is a pity that the poor father is unable to bring up his children when he is not able to feed them. After all, in our country, we have to show respect for them. We are sorry to note that the Pay Commission has taken father and mother with two children as a unit. A definite assurance was given in this House by the hon. Minister that after the submission of the Pay Commission's Report we shall take some decision about the pensioners. I requested the Minister some time in anger and some time with folded hands to please include this in the terms of reference of the Pay Commission so that the pensioners might also derive some benefits.

We were told that the Pay Commission might consider this but that if they did not, 'we shall consider it'. Do not exclude the pensioner. It will be a grave injustice to him. The date of implementation, it has been said, should be from 1st March 1970. Something should be done to these pensioners.

Then in the polytechnics, what a happening? In a boys' polytechnic, the Professors, Principal and teachers have been recommended to be paid more. But if it is a girls' polytechnic, their counterparts there have been recommended to be paid less. What is this fine distinction? The Prime Minister of India is a lady. The ladies who are employed as Professors and teachers in the polytechnic will be getting less.

As regards the income-tax department, it has been clearly said that there is no fine distinction between classes I and II. So there should be no discrimination in service conditions. In fact all Central Government employees, the audit employees and others should be taken as one.

Coming to the question of bonus, let the hon. Minister answer with honesty and earnestness. Is it contended or is it a fact that all those working in the public undertakings are entitled to bonus, but not the defence employees, not the Central Government employees, not the railway employees, not the P. & T. employees? I stand for bonus for all employees. I cannot accept, however eloquent, the argument that the defence employees, the P. & T. employees, the workshop employees who manufacture bombs with which we defeated Pakistan, who saved our country from China are not entitled to bonus, but a person working in the Modern Bakery making bread is entitled to bonus. A person making bread will get bonus but a person making sophisticated weapons will not. I cannot accept this argument.

The Bonus Bill is being introduced again. Shri A. P. Sharma has already threatened a strike, though he will never go on strike. He only threatens. I am all for it. All Central Government employees are one. Bonus is a deferred wage. 12 months' honest work and 13

months salary—this is the slogan. Otherwise, we shall not agree.

We were assured by Shri Jagjivan Ram that another meeting is *not* ruled out. Where is that meeting? When we met in the JCM, the Cabinet Secretary, who is the Chairman of the JCM said 'I shall convey your feeling to the hon. Ministers.' When we met the Ministers, they gave us a patient hearing for 90 minutes but did not commit themselves. We were pleading our case before a constitution bench of the Supreme Court. They never said anything. Let them not adopt this attitude. Let them start negotiations with the employees' representatives on all issues, the issue of need-based minimum wage or any other issue. I am sure the employees will take a reasonable stand. Shri Sharma said, 'let us have a *via media;* let us have a compromise'. Compromise on what? Compromise with hunger, with starvation? No more compromise on this issue. If the condition of the country is bad, if the worker in the unorganised sector is getting less. . .

SHRI A. P. SHARMA: What for is negotiation, if not for compromise?

SHRI S. M. BANERJEE: Compromise not with hunger.

If they do not want to pay Rs. 314, let them say what they want to pay. Then we shall negotiate Let them pronounce what they are going to pay. Then we shall negotiate Otherwise, I can tell you, if the public undertakings, if the banks, if the private sector, can pay more, Government is bound to pay more. If the corporation employees are getting less, if the board employees are getting less, if the local bodies' employees are getting less, it is the responsibility of the Government; it is not our responsibility. If the resources question comes, we are prepared to discuss that also and indicate where from resources will come. I should also say that there is this black money, 7,000 to 10,000 crores. There are arrears of income-tax Rs. 700 crores, in addition to evasion of income-tax. In that case it is a political question. If a thermal plant worth Rs. 9 crores can be sold to Birlas for Rs. 2.75 crores, how can one say that this is not to be done? The Central Government employees are entitled to a need-based minimum wage; they have a right to live because they are salaried employees and they cannot conceal anything.

Lastly, I should request about the parliamentary staff, whether Lok Sabha or Rajya Sabha. Their working conditions are arduous. Their conditions should be looked into by a Committee under the chairmanship of either the Speaker or the Chairman of the Rajya Sabha, or both. They should also be given the right to form associations.

With these words, I request the hon. Minister to reply to our points, either today or tomorrow. They should start negotiations with representatives of employees. If that is not done. it will not be of any avail, whatever eloquence we may have got and whatever efforts Mr. Sharma may make. The Central Government employees are hungry today and the line between hunger and anger is thin and they will not rest until they achieve their objective.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): I am happy to be able to speak immediately after Mr. Banerjee because I find this is one of the rare occasions when I can say that I agree with most of what he said. It is a tragic thing that after the submission of the report by the Pay Commission, the general reaction among the services, particularly the lower categories, is one of complete discontent and the reaction is like giving a warning that if no improvement is effected, the implementation of the recommendations will not bring about what is really desired, namely, industrial peace and complete co-operation from the services.

I want to emphasise only two points. The first is about the minimum remuneration. I do not go to the extent of demanding, as Mr. Banerjee demanded, that Rs. 314 must be accepted as the

[Shri C. M. Stephen]

minimum remuneration. I am clear in my mind that even Mr. Banerjee is not serious when he puts forward that proposition. But I cannot for any reason agree with the finding of the Pay Commission, mentioned in page 58 of their report: "We have therefore not found it possible to recommend that the minimum remuneration of the Central Government employees should be fixed on the basis of the norms recommended by the 15th Indian Labour Conference." No trade unionist in the country will be able to agree with this proposition.

In 1957, 15 years ago at a joint conference it was stipulated that the minimum remuneration must be such and such, that the considerations must be such and such. After 15 years, if we are told that those norms are not acceptable you will be putting forth propositions which will have a very dangerous consequences for the working class. Therefore, on this particular question, I am absolutely sure, that irrespective of political affiliation and party differences, there cannot be any agreement with the proposition put forth by the Pay Commission at all.

This is a matter on which the working class will have to fight and demand a minimum based at least on the norms stipulated by the Indian Labour Conference. It does not stop there. After having set forth this proposition, they go on to say what exactly must be the norms to be applied and after putting forth their own clarifications, they come to a decision that Rs. 195 must be the minimum remuneration. But they say that that minimum need not be given to an employee who starts his service, on certain grounds which are absolutely faulty and unacceptable. I could have understood that if the Commission had recommended that Rs. 195 has to be given—not that it will be acceptable to us—but without giving even that and saying that only Rs. 185 will be given on the basis of presumptive considerations that anybody who comes to service at a particular age is unmarried and will not have to support anybody at all is a proposition which is fundamentally wrong. This has been amply dealt with by Mr. Pillai, one of the members of the Commission and I need not dwell further on it. Coming to poverty level, in urban areas, the Planning Commission has spelt it out to be Rs. 50 per head. For a family of four, it is very clear that there must be at least Rs. 200. Instead of that Rs. 185 is being recommended to the lowest grade employee. Let us take two cases and see the discrimination. You start the lowest grade employee on Rs. 185. Five years have to elapse before he draws the remuneration which is spelt out by the Commission as the minimum remuneration. On the other hand, you start a Class I employee on Rs. 700. In five years he drawns Rs. 900. By this departure from the fundamental principle, what is the amount you are saving? It has been calculated by Mr. Pillai that the saving is Rs. 49 crores. Is that an amount worth bargaining for in order to make a serious departure from—a fundamental principle? I am not conceding for a moment that Rs. 195 only should be the minimum remuneration. But even conceding Rs. 195, why this miserliness while dealing with the smallest employee? Let us not forget that we are dealing with human beings. We are living in troubled times when people are finding it difficult to make both ends meet. If you are not prepared to see the realities of the situation as far as human beings are concerned, no amount of sermonising that you must cooperate in the solution of national problems will have any effect at all. Sacrifice there must be, I quite understand. But it will have to be all round. With regard to certain others, there need be sacrifice only and nothing more—this is a proposition which the country will not accept at all. You say that you are starting a Class I employee on Rs. 700 because on a competitive basis with the private sector, unless you give him so much you cannot get the best talent. For that, is this the only solution? Why should the private sector continue to pay such salaries which are sky-rocketing? Why not put a restraint on that? Why should there be this ostentatious

living? Why should five star hotels come up one after the other throughout the country? Why should there be cabaret dances going on in this country? Why should these colossal buildings come up and money should be spent on them? Why should these perquisites be allowed to certain persons who are placed in high positions? When the country is suffering no citizen in this country has got the right to live at a particular stage which is beyond the reach of the vast majority of the people in this country. Any person who wants to have that sort of living is not a servant of the people. The curbing has to be done at that level.

The Commission has given a comparative statement of the ratio between the lowest and the highest. Whereas in the United States it is 1 : 8, in India it is 1 : 25. They say that this situation obtains in the developing countries. But they could cite only three developing countries. Have they made an effort to bridge the difference between the two? If there is no effort made in that direction, then nobody would be prepared to make any sacrifice at all. This is a point which I want to emphasize. A departure from the recommendations of the Indian Labour Conference is a proposition which will not be acceptable to the working class of this country, to which ever flag they may belong, to which ever political opinion they may belong.

Secondly, after having stated one particular figure as the absolute minimum remuneration with which a human being may exist, to give below that minimum of Rs. 185 is, to say the least, criminal, callous and unimaginative, and the Commission has done a thing by which it has proved itself unworthy of occupying and discharging the function which it was charged with, under the socialist pattern which we want to evolve, and it is absolutely unacceptable to us.

Thirdly, this report brings forth a picture in which what it was really charged with, namely, making proposals which would be in tune with the sort of social pattern that we want to build, that has not been discharged by the Commission. It has failed in its duty in so far as bridging the disparity between the highest and lowest paid employees are concerned.

On these three grounds the recommendations put forth by the Commission need a thorough and deep look with a view to their revision. Otherwise, even though money will be paid, the discontent will remain and the country will have to face the music again. At that time if you say the slogan "no strike", that will not be acceptable at all. The moratorium on strike and other things will be acceptable so long as the difficulties of the persons concerned are appreciated. Without that appreciation the slogan will be an empty slogan and it will fall into deaf years. With these observations, I would appeal to the Government to consider the different aspects, to consider the agony through which the lowest-paid employees are passing through.

Finally, whatever be the decision of the Government, let it be given immediately. Time has already gone by. It is incumbent on the Government to apply themselves to the task of giving a final decision on this. Whether it be by discussion or without discussion, the final decision which according to them will give satisfaction to the employees to a certain level, because full satisfaction is not possible, let that decision be announced soon after their deliberations on the Pay Commission Report.

SHRI RAJA KULKARNI (Bombay—North-East): Mr. Chairman, as a trade union worker, I disagree with a number of recommendations of the Pay Commission. I know that the Commission has done a great injustice in fixing the minimum wage as low as Rs. 185 and the justification given for it was also not proper. Therefore, there is every justification for demanding that this should be rejected and that the Government should come to the rescue of the poor-paid employees. The recommendations of the Pay Commission need serious revision, so far as this aspect is concerned.

[Shri Raja Kulkarni]

This minimum of Rs. 185 is not at all acceptable. The whole argument of the Pay Commission is not at all convincing.

I also do not agree with the Pay Commission regarding its recommendation relating to retrospective effect and also about a number of other things, including the job differentials, the annual rates of increments, etc. But at the same time there is one factor which none of us, whether we are trade unionists or Members of Parliament or social workers or politicians or members of parties, can forget and that is that during the last 10-12 years, a chaos has been created about service conditions, not because of any intention of any Minister or of the Cabinet, but circumstances have been growing very rapidly as a result of which there has been not only an increase in the numerical strength of the Government employees but also a qualitative change in the composition of Government employees.

At the time of the Second Pay Commission, in 1958-59, there were hardly 17½ lakh employees But in 1971, when the Third Pay Commission took up the matter into their hands, the strength of the employees was about 30 lakhs. There was about 71 per cent increase in the strength of employees. There was not only an increase in the numerical strength but there was also a complete qualitative change in the composition of the employees We should not forget that. At the time of the Second Pay Commission, there were more Class IV employees than Class III employees. There were about 9½ lakh Class IV employees at that time and about 7 lakh Class III employees. That was the situation at the time of the Second Pay Commission. At the time of the Third Pay Commission, the number of Class IV employees was about 13 lakhs while the number of Class III employees was about 15 lakhs The whole picture changed. You will find that all this increase during the last 12 years has been more in the service employees, in the higher category of employees.

During the last 14 years, the percentage of the Class IV employees has gone up by hardly 36 to 37 per cent while the percentage increase in the case of Class I employees has gone up by more than 200 per cent and in the case of Class II employees, it has gone up by about 118 per cent. This has brought about a number of complicated problems.

The Second Pay Commission tried to bring about a system out of chaotic conditions of the wage-structure. In 1957-58, they grouped all the employees at that time into 140 pay scales But because of the change that has taken place both in the number and the quality of service employees during the last 14 years, what has happened is that the pay-scales, in 1971-72, increased from 140 to 500 pay-scales. It was mostly because there were people who came from the scientific and special and professional sides. The science cadre came up; the economic cadre came up; all the various specialised service cadres came up. IAS cadre was already there. Now, the number of pay-scales had gone up. Then perquisites had gone up The chaotic conditions were created This is not only the situation with respect to Government employees taken together as one group but it is so even inside the workshop employees of the Government, mostly the Defence depots, the railway workshops and Posts & Telegraphs where more than seven lakhs of employees who are blue-collared employees, who come under the Factories Act and factory regulations. Out of 30 lakhs, more than seven lakhs of employees are working in these workshops. I am taking only these blue-collared workers. There also, the change in their composition has taken place. At the time of Second Pay Commission, 40 per cent were unskilled workers in these workshops of three or four major departments of Government. The percentage of unskilled people in these government workshops at present is hardly 27. At the same time we find that the highly skilled category which was three per cent in 1957-58 is now 10 per cent. The rate at which this cate-

gory of highly skilled and skilled workers is going up in these workshops is quite high. This change in the composition tells on the nature of work, the system of job assignment, job evaluation. All the individual discontent had come up during the last eight or ten years not only because they were not getting adequate money but also because of the treatment, because of the relationship, at the spot level, at the machine point. All these had created a lot of problems. Taking all these chaotic conditions into consideration, it cannot be said that this whole report of the Pay Commission is nothing but a scrap. It is an humble attempt, in spite of some mistakes to put a system into chaos. I violently disagree with many of the recommendations. But where do we stand if the Pay Commission's report is to be thrown into the dust-bin? That is the point. It is no use wasting our time in explaining the situation as to what constitutes the minimum wage. We have been arguing that. I have myself argued before industrial tribunals. The tribunals have not accepted our concept of norms—neither of living wage nor fair wage nor minimum wage nor need-based minimum wage. Awards have been given. We were not satisfied and yet we tried to put up with those and at the proper time we have continued our fight for higher wage. Therefore, the point today is not explaining what injustice has been done. The explanation is enough. The question is, whether we can get Rs. 314 as the minimum wage. The distance from Rs. 185 to Rs. 314 is far wide. Can we, and to what extent, shorter the distance, that is the question.

Otherwise, we would be misguiding the workers. Let us be more realistic. After all, what exactly does the pay structure reflect? The pay structure and the wages are ultimately the product not only of the demands that are made but of the combination of three things. The demands of the workmen which reflect their needs no doubt. Needs are processed through the factors of economic feasibility and social acceptability. If Government has said or if the report has said that the cost to the exchequer because of three interim reliefs which have been given, has been Rs. 175 crores and that the cost of the new increase as a result of pay fixation, as a result of bringing down the number of trades from 140 which was suggested by the Second Pay Commission, to 80—a number of jobs are to be upgraded—and taking all the factors into consideration, the additional burden, is Rs. 145 crores, do we not consolidate our position and make out a proper case? Can we not give proper direction to our workmen to take things in the right spirit, in the context of the present situation? According to me, we can easily say to the Government that we do not agree with the Pay Commission's report, therefore, do not take a decision. The second is: negotiate with us.

Now collective bargaining has been going on in the private sector. Collective bargaining has been going on in the public sector undertakings. I would request my friend, Mr. Banerjee or all those connected with the Defence, the Railways or any other organization that the time has come that we ponder more over this whole group of 30 lakhs employees. I was listening to Mr. Banerjee and I agree with him. If I were in his place, I would have also pleaded that the Defence employees should not be differentiated from the employees of other public sector undertakings. He is perfectly right. But it is very difficult to get justice to the Defence employees, to the Posts and Telegraphs and to the Railways, if they are taken along with the bandwagon of all other administrative employees of the Government. Let them be taken as a separate category—the 15 lakhs of employees. It is not necessary that all the 30 lakhs employees should be put together and their service conditions should be similar. We can get some additional benefit for the 15 lakhs employees because they are production employees, because, they are industrial employees. In respect of the demand for bonus, they are asking only for these employees. They are not asking for all the 30 lakhs employees of the Government. Similar is the case with regard

[Shri Raja Kulkarni]

to wage increase. Similarly, the minimum wage has to be revised. I would also suggest that a representation should be made to the cabinet to have a decision that they should revise this Rs. 185 to a large extent. At the same time nothing is mentioned as to how long these new pay scales and other pay structure should remain. The validity period is to be decided. The employees' organisations can say, "Immediately on the expiry of one year we want that the Government should sit with us No further commission, no other arbitration, nothing of the kind. We shall negotiate". Sir, a bird in hand is better than two in the bush.

MR. CHAIRMAN: I have to inform the House that it has been decided that the House will sit upto 7 O'clock.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): सभापति जी, भारत के भाग्याकाश पर इस समय आर्थिक संकट के गहरे काले बादल मंडरा रहे हैं उन की छाया में वेतन आयोग की रिपोर्ट पर यह चर्चा कुछ अवास्तविक और अयथार्थवादी मालूम होती है। आर्थिक सकट के लिए न तो भारत और पाकिस्तान युद्ध उत्तरदायी है और न सूखे को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सरकार की नीतियां, जिनके अन्तर्गत मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी है, घाटे की अर्थ व्यवस्था का अवलम्बन किया गया है, अनुत्पादक व्यय में बढ़ौतरी हुई है, आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगाए गए है—वर्तमान संकट के लिए जिम्मेदार है। आज देश महगाई, अधिक मजूरी और फिर महगाई— इसके दुष्चक्र में फंस गया है। मै जानना चाहता हूं इस चक्र मे से निकलने के लिए सरकार के पास कौन सी नीति है? यह खेद का विषय है कि पिछले 26 वर्षों में हम मूल्यों और मजूरी के बारे में कोई राष्ट्रीय नीतिका निर्धारण नहीं कर सके। मूल्यों की अलग चर्चा होती है, मजूरी का अलग से विचार किया जाता है, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समस्यायें पृथक चश्मे से देखी जाती हैं और राज्य कर्मचारियों को दूसरे तराजू पर तौला जाता है। जो मजदूर संगठित नही है उनका कोई पुरसांहाल नहीं है। इसी का परिणाम है कि देश आज ज्वालामुखी के कगार पर बैठा है। लाल किले से जारी की गई अपीलें जनता के रोष और क्षोभ को शांत नही कर सकती है, उस के लिए ठोस नीतियां अपनानी पड़ेगी। मेरी मांग है सरकार प्राइस वज पर एक नेशनल पालिसी का निर्धारण करे, उसकी मुख्य बाते इस प्रकार होनी चाहिए—पहली चीज तो यह जरूरी है कि मूल्यों को 71 के स्तर पर लाया जाये जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, सरकार मूल्यों मे कमी करे और आवश्यक वस्तुये 71 के मूल्यों पर जनता को उपलब्ध करने का प्रबन्ध करे। दूसरी बात—अब आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के सिद्धान्त से पीछे जाने का समय नही है। क्या 15वे श्रम सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधि नही था? क्या उस समय सरकार की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी? ? क्या देने की क्षमता का प्रश्न उस वक्त खड़ा नही हुआ था? न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे क्रमश: लागू करने के संकल्प की इस चर्चा में घोषणा की जानी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि पे-कमीशन यह तो कहता है कि उस श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार न्यूनतम वेतन 314 रु० होना चाहिए और फिर

कहता है कि वह नहीं दिया जा सकता । आगे कहता है कि हमारी गणना के अनुसार 196 रुपये आज की स्थिति में कम से कम वेतन होना जरूरी है लेकिन जब देने के वक्त होता है । तो 185 रुपए ही देता है । कमिशन का यह दिवालिया पन समझ मे नही आता । आपको देख कर हंसी आयेगी कि कमिशन ने जो गणना की हैं उसके अनुसार कमिशन का कहना है कि दिल्ली, बम्बई, कलकता जैसे शहरों मे 14 रुपए 71 पैसे मे मकान मिल सकता है—मैं जानना चाहूगा कि वह मकान कहा मिलेगा ? कमिशन क्या ऐसी मकानो की व्यवस्था कर सकता है या व्यवस्था की है ? क्या उन्होंने कहीं जाकर देखा भी है ? गैरेज भी 14 रुपए मे नही मिल सकता । है । पार्लमेन्ट के मेम्बर कन्सेशन रेट पर गैरेज पाते है लेकिन उसका किराया 14 रुपए से ज्यादा है ।

पे कमिशन यह भी कहता है कि 50 पैसे मे एक समय का भोजन मिल सकता है । वह कौन सा भोजनालय है जो 50 पैसे मे एक समय का भोजन उपलब्ध करता है ? रघुवर दयाल भोजनालय अगर कहीं चल रहा हो तो मैं भी उसका पता जानना चाहूगा । लेकिन इस गणना के अनुसार जो 196 रु० होते है वह भी पे कमिशन ने दिए नही । (व्यवधान) मालवीयजी, आप तो समझदार आदमी है लेकिन आपकी पार्टी मे जो नासमझ है उनका क्या होगा ?

दूसरी बात जो जरूरी है वह यह है कि हमें इन्फ्लेशन फ्री डीयरनेस एलाउन्स की परिकल्पना का विकास करना चाहिए तुरन्त मूल्यों को नियंत्रण करना या घटाना सरकार के बूते के बाहर की बात मालूम होती है । लेकिन कर्मचारियों को सुविधाओं के रूप मे इनफ्लेशन फ्री डी० ए० दिया जा सकता है । वह घर से दफ्तर आते हैं, आने जाने के लिए सस्ता यातायात परिवहन मुहैया किया जा सकता है । दोपहर मे सस्ते भोजन का प्रबन्ध हो सकता है । कर्मचारियो के लिए वर्ष मे सुविधाजनक दरों पर रेल यात्रा की सुविधा दी जा सकती है । बडे बडे अफ़सरों के वेतन मे उन की सुविधाओं में बहुत सी चीजे हैं, वह स्टाफ कार पर चलते है, वह लंच और डिनर भी सरकारी खर्चे पर अशोका होटल या इटरकान्टीनैटल होटल मे पाते है । उन्हें और सुविधायें भी प्राप्त है, वह सब कर्मचारियो के लिए उपलब्ध कराने का हमे प्रबन्ध करना चाहिये और इन्फ्लेशन फ्री डी० ए० के कासेप्ट पर काम कर के और कोई ठोस चीज निकालनी चाहिये ।

सभापति जी, मैं यह भी चाहूगा कि जो वेतन और मूल्यो की राष्ट्र नीति हो उस के अन्तर्गत कम से कम मजूरी और अधिक से से अधिक मजूरी का अन्तर घटाया जाय । आज यह अन्तर बहुत ज्यादा है । पे कमीशन उस को घटाने के बजाय बढाने के लिये जिम्मेदार है । अगर विषमता कम करनी है तो फिर आज को स्थिति मे जितना अन्तर है उस को चलने नही दिया जा सकता । न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अन्तर 1 और 10 का होना चाहिये । अगर आज यह करना सम्भव नही है तो हम 1 और 20 का आज लक्ष्य मान कर

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

चलें और उस पर अमल करें। लेकिन पे कमीशन ने जो कुछ किया है वह तो प्रवाह को उल्टा घुमाने जैसा है। छोटे कर्मचारियों पर बोझा अधिक, बड़े अफ़सरों के लिए सुविधायें अधिक। यह स्थिति चल नहीं सकती। कम से कम यह स्थिति हमारी उद्घोषणाओं के अनुकूल नहीं हैं। और अगर कथनी और करनी में अन्तर रहेगा तो फिर राष्ट्र निर्माण के लिए जनता का स्वेच्छा से मिलने वाला सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता।

सभापति जी, पहली बार पे कमीशन ने सुरक्षा सेवाओं के वेतन मानों का विचार किया है। यदि हम गहराई से देखें तो फ़ौज में काम करने वाले जवान और अफसर और सरकार की दूसरी शाखा में काम करने वाले कर्मचारी और अफ़सर इन के वेतनों में अन्तर है। अभी सिविल एवियेशन मिनिस्टर यहां मौजूद थे, पता नही कहां उड़ गये, एयर फ़ोर्स में काम करने वाला पायलट जो अपनी जान जोखिम में डालता है कम वेतन पाता है और एयर इंडिया का पायलट लक्ष्मी में लौटता है। दोनों हवाई जहाज उड़ाते हैं, दोनों की सेवाओं की देश को आवश्यकता है। दोनों ने वेतन मान में कहीं कोई बराबरी होगी या नही, कोई औचित्य होगा या नहीं? नई दिल्ली के सेक्रेटेरियट में काम करने वाला चपरासी आज उस जवान से अधिक वेतन पाता है जो जवान युद्ध क्षेत्र मे मोटरगाड़ी चलाता है, जो बन्दूक उठाता है। उस को भी स्किल्ड कर्मचारी, कारीगर के रूप में नहीं गिना गया है। जो साधारण जवान है वह भी बन्दूक चलाता है, वह भी बारीक हथियार का उपयोग करता है और वक्त आने पर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उस को स्किल्ड लेबर के बराबर तन्खाह नहीं दी गयी।

जहां तक अफसरों का सवाल है अगर कोई आई० ए० एस० में जाय तो जो वेतन कमीशन ने माना उस पर कितनी जल्दी पहुंच सकता है इसका अनुमान लगायें। और अगर आर्मी में जाता है तो लेफ्टीनेंट जनरल बनने में कितना समय चाहिये और कितनी जल्दी रिटायर हो जाता है। इसका भी विचार करें। दूसरी ओर जवानों और अफसरों के वेतनों में भी अन्तर ज्यादा है, यह भी असंतोष को जन्म दे सकता है। है। इस पहलू पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। केन्द्रीय कर्मकारियों को सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स देने का एक फार्मूला है, उस के आधार पर जनसंख्या के अनुसार कर्मचारियों को मकान भत्ता दिया जाता है। लेकिन जनसंख्या के साथ क्या महंगाई का विचार नहीं होना चाहिये? इंदौर और जबलपुर की तुलना में ग्वालियर अधिक महंगा शहर है मगर क्यों कि जनसंख्या थोड़ी सी कम है ग्वालियर के कमचारी 'बी' ग्रेड से वंचित कर दिये गये। सभापति जी, क्या ग्वालियर के केन्द्रीय कर्मचारियों से यह कहूं कि परिवार नियोजन के अभियान का विरोध करें और दो, या तीन बच्चे के बजाय जनसंख्या बढ़ाने में लग जाओ

तभी आप को 'बी' ग्रेड मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है ? सभापति जी, वैसे भी कर्मचारी अब दो या तीन की बात नहीं मान रहे हैं क्यों कि वह देखते हैं कि लाइन में लगाने के लिए उन्हें बच्चे चाहिएं । एक राशन की लाइन के लिए, दूसरा चीनी की लाइन के लिए तीसरा तेल की लाइन के लिए, चौथा सीमेंट की लाइन के लिए, पांचवां पानी की लाइन के लिए और छठा इन सब की देख भाल के लिए वह लाइन मे लगे हैं या कही गिल्ली डडा तो नही खेल रहे हैं ।

सभापति जी, पे कमीशन ने सिटी कम्पेसेटरी अलाउन्स के बारे में सेन्सस के रजिस्ट्रार जनरल की सिफारिश का उल्लेख किया है और यह कहा है कि अर्बन एग्लोमरेशन को भी ग्रेडेशन के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान मे लिया जाना चाहिए । नगर फैल रहे है, गांव नगरों के साथ जुड रहे है , कर्मचारी दूर-दूर से काम करने के लिए आते हैं उन पर भी महंगाई का असर होना है, उन को भी लाभ मिलना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि पे कमीशन की रिपोट के सम्बन्ध में जब अतिम निर्णय लिया जायगा तो अर्बन एग्लोमरेशन की बात ध्यान मे रखी जायगी और शहरी एरिया और कंटोनमेट, शहरी एरिया और ग्रामीण क्षेत्र, इस का अन्तर नही किया जायगा । मैं तो चाहता था कि पे कमीशन महगाई को भी एक आधार मानता लेकिम उसने यह मानने से इन्कार कर दिया है इस दृष्टि से मै समझता हूं उस की सिफारिश प्रतिक्रियावादी है । लेकिन फिर भी पे कमीशन की सिफारिश की चौखट के अन्तर्गत कुछ शहरों के कर्मचारियों को राहत मिल सकती है उस पर विचार करना चाहिए ।

सभापति जी, अपने भाषण को उपसंहार की ओर ले जाना चाहता हूं । रेलवे कर्मचारियों को पे कमीशन की परिधि से बाहर निलकाने का प्रयत्न होना चाहिए । रेल कर्मचारियों के लिए मे कमीशन नही, वेज बोर्ड बनाने की जरूरत है । रेल मंत्री कहते हैं कि उन की इतनी कैटेगरीज है कि वह हर एक का अलग अलग विचार नही कर सकते । आखिर वह एक कर्मशियल कन्सर्न है, लाभ और हानि की दृष्टि से चलती है । रेल मजदूरों को अधिकार होना चाहिए कि वह कलेक्टिव बारगेनिंग कर सकें, सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग कर सकें । मैं लोको कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं उन्ही ने रेल मंत्री को झुका लिया । वह बात करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर बात करनी पड़ी । अगर लोको कर्मचारियो से पहले बात करने को तैयार हो जाते तो हड़ताल नही होती । और मैं चेतावनी दे रहा हूं कि कर्मशियल कलकर्स असंतुष्ट है, असिस्टेंट मास्टर परेशान है, गार्डों के मन में असतोष की ज्वाला धधक रही है ।

17 hrs.

मै यह भी चाहता हूं कि लोक सभा और राज्य सभा के कर्मचारियो के बारे मे भी, उनके वेतन मानों के बारे में उनकी सेवा की शर्तों के बारे मे विचार होना चाहिए । यह ठीक है कि पे कमिशन यह नही कर सकता था । लेकिन कोई विशेष समिति बनाई जा सकती है, बननी चाहिए जो कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखे, उनकी नियुक्ति किस ढंग से होती है, उनकी तरक्की किस तरह की जाती है, उनकी क्या कठिनाइया हैं, ओवर टाइम उन्हें ठीक मिलता है या नही मिलता है, इन

[श्री अटल विहारी वाजपेयी]

सब प्रश्नो पर विचार करने के लिए कमेटी बनाना जरुरी है। मैंने उस दिन कहा था उत्तर प्रदेश मे पी ए सी काड के बारे में कि इसका यह भी एक कारण था कि पी ऐ सी के जवानो से जो ओवर टाइम काम लिया जाता है उसके लिए नियम बना हुआ है कि महीने मे दस रुपए से ज्यादा ओवर टाइम उनको नहीं दिया जाएगा, ओवर टाइम का घटो से कोई सम्बन्ध नही है, ओरवर टाइम का काम से कोई नाता नही, यह अन्याय अब नही चलेगा।

स्वाधीनता दिवस पर बडी बडी अपीले की गई है। प्रधान मत्री ने कहा है कि अग्नि परीक्षा मे तप कर सोना कुदन बन जाता है। लेकिन उन्हे याद रखना चाहिए कि अग्नि परीक्षा मे पीतल गल भी जाता है। सोना कुदन बनेगा लेकिन जो पीतल है, जो सोने की चमक से भी ज्यादा आखो को चौंधिया देता है वह अग्नि परीक्षा मे से नही निकलेगा, वह परीक्षा मे गल कर वह जाएगा। आज पीतल गल रहा है और सोने की तलाश हो रही है। प्रधान मत्री पहले स्वय को परीक्षा मे उत्तीर्ण करे और फिर देश का परीक्षा मे पडने के लिए आहवान करे तब तो देश उनके आहवान का उत्तर दे सकता है लेकिन इह समय जो उनकी चमक धुधरी हो रही है और याद रखना चाहिए उनको कि बोनस के सवाल पर, यूनतम वेतन के सवाल, पर सौ फीसदी महगाई भत्ते मे, वृद्धि के सवाल पर केन्द्रीय कर्मचारी असन्तुष्ट है, राज्य कर्मचारी आन्दोलत हैं और देश को इनके आन्दोलन का सामना न करना पडे इसलिए एक नैशनल पालिसी आन प्राइसिस एड वेजिज कोई इवाल्व करने की आवयश्कता है। सरकार टुकडों मे इस सवाल को न देखे, तसवीर को पूरे रूप मे देखे और हल निकालने का प्रयत्न करे।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर): मैं सदन मे अपने साथी माननीय सदस्यो के भाषणो को बडे ध्यान से सुनता रहा हू। मैं इस आशा मे था और अब भी मेरी मान्यता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के वेतनो के पुनरीक्षण के प्रश्न को राजनीतिक शतरग की कोई गोटी नही बनाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे विरोधी दलो के जो नेता हैं वे कोई मौका छोडना नही चाहते हैं जबकि वे कुछ ऐसी बात न कह दे जिसका चाहे मुल्क के भविष्य पर या सरकार के द्वारा योजनाओ के कार्यान्वियन पर कुछ बुरा असर न पडे। अभी वाजपेयी जी के भाषण को मै बडे ध्यान से सुन रहा था। मैं पहले उनका नाम इसलिए लेता हू कि उनकी भाषण कला खास कर हिन्दी की, मै एक गर्व का विषय मानता हू। आपने बिना समाजवाद का नाम लिए हुए सभी समाजवादी बातें कही है और वेतन आयोग के प्रश्न पर इतना समाजवाद को उछाला, सामान्य आर्थिक प्रश्नो म उसका एक चौथाई भी अगर समाजवाद इनकी नीतियो मे रहता तो मेरा ख्याल हैं कि देश का बडा कल्याण हो गया होता लेकिन जहा तक सरकारी कर्मचारियो का प्रश्न है—यह नही कि मैं आपसे अलग राय रखता हू इस प्रश्न पर—आपका समाजवाद इतना उछल पडा कि हम लोग आश्चर्य चकित रह गए।

श्री बाजपेयी ने कहा कि जो खर्चा बढ़ा है, महंगाई हुई है, वह इसलिए हुई है कि अनुत्पादक व्यय किया गया है। सूखे की वजह से वह नहीं हुई, पाकिस्तान के साथ लड़ाई की वजह से वह नहीं हुई तो अनुत्पादक व्यय होता क्या है? सूखे में रिलीफ के वास्ते किया गया खर्च अनुत्पादक नहीं है युद्ध में किया गया खर्च अनुत्पादक नहीं है तो अनुत्पादक व्यय किसको वह कहते हैं? पता नहीं अनुत्पादक व्यय की इनकी परिभाषा क्या है? आपको कुछ और बातों को समझाना है इस वास्ते आप उस विषय बिन्दु से इन्कार करते हैं लेकिन इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि अनुत्पादक व्यय की वजह से हमारे यहां महंगाई आई है, इनफ्लेशनरी प्रैशर हुए हैं। मैं समझता हूं कि उनकी बातें किसी को, देशको धोखे में नहीं डाल सकती हैं, सदन को तो हर्गिज नहीं।

श्री बनर्जी ने कहा कि हम हंगर और स्टार्वेशन के साथ कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारे देश में यह नारा होना चाहिए कि हम भूखे रहने से इकार करें, हम नंगे रहने से इन्कार करे। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि आज इस देश मे तथा संसार के सारे अविकसित देशों में हम हंगर, स्टार्वेशन और नेकिडनैस के साथ कम्प्रोमाइज करके चल रहे है। वह एक ऐसी वस्तुस्थिति है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता है। यह बहुत स्पष्ट है। इसलिए कोई भी बात हमें ऐसी नहीं बोलनी चाहिए जिससे भावना का उभाड़ हो। क्षणिक तकलीफ की वजह से हम बड़ी बड़ी बातों को भूल जाएं और अपने देश की वास्तविक आर्थिक अवस्था को नजरअंदाज करें, यह ठीक नहीं है।

मैं एक एक सदस्य के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मैं कुछ सामान्यमान्यताओं के बारे में वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। एक जमाना था जब राज्य का रोल केवल नियामक यानी रेग्युलेटरी हुआ करता था। फिर एक जमाना आया जान स्टूअर्ट केवल मिल, कार्लाइल और मार्क्स का और उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट केवल नियामक नहीं रहेगा वह इंस्ट्रूमेंट आफ चेंज होगी और हम राज्य की शक्ति से समाज में परिवर्तन करेंगे और होना चाहिए। हमारे देश में अंग्रेज आए। उन्होंने जो व्यवस्था हमारे देश को दी वह कोलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की दी। वह औपनिवेशिक प्रशासन था। आज हमारे देश में औपनिवेशिक प्रशासन नहीं है, एक दूसरे किस्म का प्रशासन है जिसकी नीति का उद्देश्य यह है कि हम देश का विकास करें, हम अपने यहां आर्थिक विकास करे और साथ साथ सामाजिक न्याय का विस्तार करते जाएं। मैं बार बार अपने से पूछता हूं और एक सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के नाते और बिहार में इस विभाग का एक छोटा सा मंत्री रहने के नाते मैं अपने से पूछ रहा हूं कि आज का जो हमारा सामान्य प्रशासन है क्या वह सचमुच में आर्थिक विकास का, ग्रोथ विद जस्टिस का कोई इंस्ट्रूमेंट है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यह मामली प्रश्न नहीं है। यहां हम सब भाषण करते हैं, बातें करते हैं हमारे जो ग्रैंडियोस प्लांज बनाने वाले हैं वे सुन्दर सुन्दर शब्दों में प्लांज को बना देते हैं उन सामान्य प्रशासकों से हमारी नीतियों का कार्यान्वित कितनी होती हैं और कितनी हम उसकी उपलब्धि पाते हैं, यह हमारे मुल्क में सब जगह

[श्री नवल किशोर सिंह]

जाहिर है, पार्लिमेंट की किताबों में लिखा हुआ है । सामान्य प्रशासक, फर्स्ट क्लास फर्स्ट एम ए सुन्दर से सुन्दर भाषा में प्लांज तैयार कर देते हैं, अच्छी से कच्छी अंग्रेजी लिख लेते हैं और जब प्लांज बन जाते हैं और फेल हो जाते हैं तो प्लांज की फेल्योर को सुन्दरतम अंग्रेजी भाषा में कारण देकर वे एक्सप्लेन करते हैं बीत कुछ नहीं है । उनकी अंग्रेजी प्लान बनाने में काम आती है और फिर उसकी फेल्योर को एक्सप्लेन करने में और बहुत ही सुन्दर लैंगुएज में वे इस काम को करते हैं मैं तो उनकी लैंगुएज पढ़कर मोहित हो जाता हूं । इस फारेन लैंगुएज को मैं भी पढ़ने वाला हूं । उनकी भाषा को पढ़कर तबीयत खुश हो जाती हैं। ऐसी बढ़िया भाषा में वे कुछ करते है कि क्या हमारी प्रधान मंत्री या हमारा मंत्री कर सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे सामान्य प्रशासको का बोझ मुल्क कब तक बरदाश्त करेगा ? हम ये सब चीजें पिछले साल से देखते आ रहे है । सारा जिम्मा आपने इनको दिया हुआ है । आज 51,000 करोड़ रुपये की योजना बना करके आप मुल्क की किस्मत को बदलने वाले हैं । लेकिन आपने इनका कोई विकल्प नही निकाला है, यह हमारे मुल्क के लिए एक चिन्ता की बात है ।

हमारे यहा स्पेशलाइज्ड सर्विसज की कोई कद्र नही है, हालाकि हमार ब्रिलिएंट लडके एयरफोर्स इंजीनियरिग और मेडिकल में जाते है । जवाहरलाल जी ने एक बार यही बात कही थी । अभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि एयर फोर्स और एच० ए० एल० के इंजीनियरों को सिविल एवियशन वालों के मुकाबले मे क्या तन्ख्वाहें मिलती है । जहां तक डाक्टरों का सम्बन्ध है, एक डाक्टर को फर्स्ट प्रोमोशन 48 साल की उम्र में मिलती है जबकि आई ए एस के सदस्य 37 साल की उम्र में ही फर्स्ट प्रोमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं । हम लोग जानते हैं कि जिन लड़कों को मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता है, वही बी० ए०, बी० एस सी० और एम० एच ए० आदि पास कर के आई० ए० एस० आदि में जाते हैं ।

डा० राव का इंस्टीट्यूट कनाट प्लेस में है । वहां सैकड़ों लड़के लड़किया कोचिंग के लिए जाते हैं । आप किसी से बात कीजिए ; उन लोगों को हमारे गांवों के बारे में कोई जानकारी नही है । अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास एम० ए० भी हमारें गांवों के बारें में दो चार बातें बता दे तो मैं पार्लियामेंट की मेम्बरशिप से इस्तीफा देन के लिए तैयार हूं । वे सब कल आई० ए० एस० होंगे । मसूरी में छोटी सी ट्रेनिंग दे कर सरकार उन को मुल्क के सिर पर बिठा देगी । क्या इस तरह हमारे देश का प्रशासन चलने वाला है ?

जहां तक स्पेशल पे का सम्बन्ध है, सवाल यह है कि वह किस किस बात के लिए दी जाती है । अगर कोई आफिसर फील्ड में रहेगा तो उस को स्पेशल पे नही मिलगी । अगर वह टूर पर जायगा और धूप तथा बरसात में काम करेगा, तो उस को स्पेशल पे नही मिलेगी । लेकिन अगर वह स्टेट सैक्रेटेरियेट या सैंट्रल सैक्रेटेरियेट के एयर-कन्डीशन्ड रुम में आ कर बैठ जाएगा, तो उस को दो सौ रुपये से पांच सौ रुपये तक स्पेशल पे मिलने लग जायेगी । इस लिए मेरी समझ में नही आता है कि वेतन आयोग ने किस तरह स्पेशल पे की सिफारिश कर दी है । मैं क्लासेज के खिलाफ नही हूं । मेरे बहुत से रिश्तेदार क्लार्क और एसिस्टेंट हैं । सवाल यह है कि इस वक्त बी० ए० या एम० ए० पास करनें के लिए

यूनिवर्सिटी में जनरल एजूकेशन प्राप्त करने के लिए, जो मैड रस हैं, सरकार उस को किस तरह कम करने जा रही है । अगर हमें काम करने वाला आदमी चाहिए, तो वह तो वर्कशाप से ही पैदा होता है । अगर वर्कशाप का स्केल कम हो और यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्तियों का स्केल ज्यादा हो तो मुझे माफ किया जाये, यह उत्पादक कार्य करने वाले व्यक्तियों को तैयार करने का तरीका नहीं है ।

पे कमीशन ने कहा है कि चूंकि प्राईवेट सैक्टर में ज्यादा तन्खवाहें दी जाती हैं, इस लिए हमें भी अपने कर्मचारियों और अफसरों को ज्यादा तन्खवाहें देनी पडेंगी। मेरा कहना यह है कि सरकार प्राईवेट सैक्टर से कम्पीट नहीं कर सकती है । प्राईवेट सैक्टर तो दस हजार रुपया महीना दे सकता है । इसके साथ साथ अपने कर्मचारियों के बेटे बेटियों को एपायंट कर सकता है, जो स्कूल में पढ़ते है, और उनके नाम पर तन्खवाह ड्रा कर सकता है । क्या सरकार उस के साथ कम्पीट कर सकती है ? सरकार तो एक ही काम कर सकती है कि वह प्राईवेट सैक्टर को दस हजार रुपये तन्खवाह देने से रोके, ताकि वह खुद भी ज्यादा तन्खवाहें देने के लिए मजबूर न हो । लेकिन वह यह बात भूल जाये कि वह तन्खवाह के बारे में प्राईवेट सैक्टर के साथ कम्पीट कर सकती है ।

मेरा निवेदन है कि डाक्टरों की समस्याओं की ओर इस देश का ध्यान जाना चाहिए । मेरा सुझाव है कि सिविल एसिस्टेंट सर्जन का एक स्पेशल पे स्केल होना चाहिए और उनकी क्लास वन सर्विस का पे स्केल आई० ए० एस० का होना चाहिए वरना हम इस देश के डाक्टरों से काम नहीं ले सकते है ।

चपरासियों, चौकीदारों आदि के लिए यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे छुट्टी ले कर नई योग्यता और स्किल प्राप्त कर सकें और अपने प्रास्पेक्टस को बेहतर बना सकें ।

सरकार द्वारा कर्मचारियों से हाउस रेंट की रसीद ली जाती है । कोई मकान वाला रेंट की रसीद नहीं देता है, जिस से कर्मचारियों को कठिनाई होती है । इस लिए कम से कम एक हजार रुपये तक तनख्वाह पाने वाले के लिए हाउस की रसीद का कोई प्रावधान नहीं रहना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सभापति महोदय, आज हमारे नेताओं में राजनीति से तात्कालिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति बढ गई है । मैं चाहता हूं कि श्री वाजपेयी गावों की जनता के बीच में यह बात कहें कि चपरासी को 314 रुपये तन्खवाह मिलनी चाहिये । और अगर तन्खवाहों में बीस गुना का अन्तर रखना है, तो उस के हिसाब से लगभग सात हजार रुपये की तन्खवाह होती है । आदमी पार्लियामेंट में जो बात कहे, वही बाहर जा कर कहे । अगर कोई सदस्य पार्लियामेंट में साढ़े उन्तीस लाख कर्मचारियों को खुश करने की बात करता है, तो वही बात उस को बाहर जनता में भी करनी चाहिए । यह ठीक है कि प्रैस वाले तारीफ करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की बड़ी वकालत की है । लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जनता में बाइस करोड़ ऐसे लोग हैं, जो सिर्फ पैंतीस पैसे रोज कमाते हैं ।

एक माननीय सदस्य. उन को भी दो । कौन मना करता है ?

श्री मूलचन्द डागा : पे कमीशन ने कहा है :

"The Commission will be required to enquire into and make recommendations on.....

(3) The Commission will make recommendations having regard, among other relevant factors, to the economic conditions in the country, the resources of the Central Government and the demands there on, such as, those on account of development planning, defence and national security, the repercussions on the plans of the State Governments and the public sector...."

और आज देश की हालत क्या है ? इस मे कहा गया है

"A household survey conducted by the National Council of Applied Economic Research in 1962 showed that 1 per cent of household enjoyed 10 per cent of the total income while the bottom 15 per cent of the household claimed only 4 per cent.

"Another study conducted by the Reserve Bank showed that the number of Indians living in rural areas in conditions of absolute poverty increased from 52 per cent of the rural population in 1960-61 to 70 per cent in 1967-68. So, these reports of studies have serious limitations....."

जो लोग साढे उन्तीस लाख सरकारी कर्मचारियो के बारे मे यह बात कहते है, वे उस बात को जनता के सामने भी कहें । तब उन्हें पता चलेगा कि इस बारे में जनता की प्रतिक्रिया क्या है । लेकिन जनता के सामने यह कहा जाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों पर बहुत पैसा खर्च कर रही है ।

प्रधान मत्री ने कल लाल किले के सामने जो भाषण दिया, उस के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वह पीतल है, जो आग मे गल जायगा । माननीय सदस्य को बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए । उन्हें अर्थ का अनर्थ नही करना चाहिए । प्रधान मत्री ने जनता की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा कि वह इन कठिनाइयो का मुकाबला कर सकती है, उस मे बहादुरी और हिम्मत है और सोना आग मे तप कर कुन्दन बनता है । माननीय सदस्य ने इस बात का कोई और ही अर्थ निकाल दिया, जिस पर कुछ लोग हसने लगे । प्रधान मत्री ने तो यह कहा था कि जनता मुसीबतो का सामना कर सकती है और वह हिम्मत के साथ आगे बढे । (व्यवधान)

माननीय सदस्य साढे उन्तीस लाख लोगो की बात करते है । क्या यह एक अलग प्रिविलेज्ड क्लास बन जाएगी ये जो साढे उन्तीस लाख सरकारी कर्मचारी, कुछ मत्री एम० पीज० और एम० एल० एज० हैं, क्या इन का एक अलग वर्ग-प्रिविलेज्ड क्लास-बन जायगा, क्या उन्ही के लिए सब कुछ करना चाहिए और बाकी ५६ करोड जनता के लिए कुछ नही करना चाहिये चाहे वह फैमिन से पीडित हो (व्यवधान)

जहा तक ओवर टाईम एलाऊंस का सम्बन्ध है, मैंने इसके कुछ आकडे देखे है । कई लोगों ने पे कमीशन के सामने कहा कि

गवर्नमेंट सर्वेन्ट को ओवरटाईम एलाउंस नहीं मिलना चाहिए। ओवरटाइम में क्या हुआ जब मैंने आंकडे तैयार किए तो मुझे मालुम हुआ कि कई करोड रूपये बैंकों के नेशनेलाइजेशन में ओवरटाइम के आप ने दिये इन विरोधी भाइयों को और कुछ नहीं मिला तो ओवरटाइम की बात ले कर उन को उकसाने लगे जहां देखो वहां उकसाने की बात है सरकार इस बात के लिये सतर्क है कि तनख्वाह बढ़ानी है । लेकिन केवल साढे उन्तीस लाख लोगों को लेकर उनको उकसाना कि हम तो तुम्हारी बड़ी वकालत करते है, मैं कहता हूं कि वकालत करने वाले लोगों जरा गांवों में जाकर इस बात को कहो तो पता चले जरा हिम्मत कर के जाओ और वहां कहो इस बात को (व्यवधान) बैंक नेशनलाईजेशन के सिलसिले मे मैंने आकड़े इकट्ठे किए तो मालूम हुआ कि 1959 के अन्दर 405 करोड़ रूपया ओवर-टाईम का दिया . 1970 में 486 करोड़, 1971 मे 614 करोड और 1972 में 711 करोड़ रूपय ओवरटाईम के दिये (व्यवधान) ठहरिये जरा बात सुनने की कोशिश करिय अगर तर्क मे उत्तर नही दे सकते तो आवाज मे किसी को दबा नही सकते हो मैंने एक प्रश्न किया कि ओवरटाइम 1971-72 मे दिया है उस के उत्तर मे उन्होंने बताया कि 79 लाख रूपया ओवरटाइम के रूप मे दिया है-सारे के सारे गवर्नमेंट स्टाफ की हालत यह देखिए कि कितना तो बढ़ता जाता है ओवर-स्टाफ्ड होने के आकडे मैं आप को बताता जाता हूं कि किस प्रकार से इनकी सख्या बढ़ी है -1956 में जहां स्टाफ था 1.86 लाख वहां 1972 में वह हो गया 2.84 लाख/52.7 प्रतिशत स्टाफ बढ़ गया और इतना स्टाफ बढने के बाद में तनख्वाह कितनी बढ गई है फिर ओवर स्टाफ भी और यह सब कुछ होने के बाद कहा जाय कि ओवर टाइम और दिया जाय पे कमीशन ने कहा कि ओवर टाइम किस को मिलता है ? कुछ लोग जो क म नही करते हैं उन को मिलता है ।

जब हम डिस्पैरिटी रिमूव करने को, विषमता को कम करने की बात करते है तो वैसी हालत में कुछ क्लास आप की ऐसी हो जो 35 सौ रूपये तनख्वाह पाए उन के बच्चे कलेक्टर बने और कुछ क्लास ऐसी हो जिस के बच्चे कुछ भी न बन सकें यह क्या है – आप देखें आप के इस तनख्वाह बढ़ाने पर कितना असर राज्यों पर और लोकल बाडीज पर पड़ता है ! मैं कहता हु इन को बढाने हैं तो राज्य सरकारों के जितने कर्मचारी है और म्युनिसिपैलिटियों के जितने कर्मचारी हैं उन की भी बढाइए, सब की बढ़ाइए ..... (व्यवधान) ..... जितनी आप की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनकी भी बढाइये ... (व्यवधान) ... मैं यह कहना चाहता था कि कुल दो लाख आदमी हिन्दुस्तान में ऐसे होंगे जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते होंगे या हिन्दी अखबार पढ़ते होंगे, उन के लिए दिल्ली की इस पार्लियामेंट में बोलने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो गांवों में जा कर इस बात को कहेंगे ... (व्यवधान) .....

वहां जाकर बदल जायेंगे । वहां और बात कहेंगे । वहां कहेंगे कि इतने प्रतिशत गरीबी है, इतने प्रतिशत महंगाई है और वहां

यह गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। तो मैं एक बात समझ नहीं पाया ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : आप क्लास टाक्स जो होती हैं, उन को मत सुनिए, अपनी बात कहिए।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, मैंने कहा कि 92.7 प्रतिशत तो थर्ड और फोर्थ क्लास सर्विसेज के लोग हैं, 5.6 प्रतिशत सैकेंड क्लास सर्वेन्ट्स है और 1.5 प्रतिशत फर्स्ट क्लास सर्वेंट्स हैं। अभी अटल बिहारी जी भाषण दे रहे थे तो पीलू मोदी जी ने एक प्रश्न किया। मिनिमम जब 314 रुपये मिलेगा तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? उस के ऊपर पहले तो कहा कि टैन टाइम्स होना चाहिए फिर बाद में कहा कि ट्वेंटी टाइम्स होना चाहिए। जब पीलू मोदी जी ने कहा कि यू आर विकमिंग मोर सोशलिस्ट तो उन्होंने टेन टाइम्स का सुधार कर के कहा कि ट्वेंटी टाइम्स होना चाहिए। एक और बीस का फर्क होना चाहिए। मैं ने हिसाब लगाया तो 315 रुपये का ट्वेंटी टाइम्स 7000 रुपये आता है। 315 रु० मिनिमम थर्ड और फोर्थ क्लास का हो तो ऊपर वालों को वह कहते है 7 हजार रुपये मिलने चाहिए। .... (व्यवधान) .... मैं एक बात कहता हूं कि 92.7 प्रतिशत के लिए हम एक बात कह कर आए है, तो जो आई० सी० एस०, फर्स्ट क्लास और सैकेंड क्लास के लोग हैं उन के साथ डिस्पैरिटी को कम करने के लिए मजबूती के साथ कदम उठाना पड़ेगा। या हम चाहते है कि उन की तन्खवाहों मे कटौती न की जाय, एक ऐसी प्रिविलेज्ड क्लास बनी रहे जिन के लड़के ही कलेक्टर बनें और दूसरों के न बन पायें? हमारे यहां कलेक्टर आता है स्टेट्स में सेंटर की तरफ से। स्टेट एम्प्लाईज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज की तन्खवाहों में फर्क है। एक ही जगह में रहने वाले, एक इलाके में रहने वाले और एक ही तरह का काम करने वाले दोनों एम्लाईज की तन्खवाहों में फर्क है। क्योंकि एक स्टेट का कर्मचारी है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है। तो यह फर्क क्यों है? यह क्या काम ज्यादा कर लेते - उन से? स्टेट्स के अंदर जो ऊपर से कलेक्टर आते हैं, मैं समझता हूं कि इस पद्धति को खत्म करना होगा। वह नाकामयाब होते हैं और काम नही कर पाते हैं।

आज का सरकारी कर्मचारी अखबर जनता के सामने जा कर कहे, या उन के आन्दोलन होते हैं, मैं समझता हूं कि जनता इस बात को जानती है कि वह निष्ठावान नही रहे, वह सेवा-भावी नही रहे वह ईमानदार नही रहे और जनता उन के मूवमेंट या आन्दोलन को कभी सपोर्ट नही करती चाहे कही भी वह हड़ताल कर ले। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट उन के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नही उठाती? जो सेक्रेटरीज है, वह केवल टाइम पर आते है, आठ घंटे काम कर लिया और हो गया जब कि 14 घंटे एक वकील काम करता है, 16 घंटे और 20 घंटे काम करता है। लेकिन इन लोगों की हालत क्या है? ...(व्यवधान).. बात यह हैं सभापति जी, कि कोई राजनीतिज्ञ अपनी जबान से किसी को नाराज नही करना चाहता। अटल बिहारी जी ने दो चार बातें कह दी, बड़ा प्रचार होगा, गरीबों की हिमायत

करने वाले बड़े हिमायती पैदा हो गए, फिर पीलू मोदी जी कह देंगे दो चार बातें, ये सारे हिमायती जी हैं ये कभी हिम्मत से यह कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं . . .

श्री पीलू मोदी (गोधरा): मैं कहने वाला था मगर आपने कह दिया ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, सरकारी कर्मचारियों की एक प्रिविलेज्ड क्लास है । आज हम एक बात कहते हैं कि ओवर टाइम उन को मिलता है, कालेजेज सारे उन के लिए, राशन उन के लिए, घूमने का उन को, हालीडेज उन को, सारी फैसिलिटीज उन को हैं। मैं कहता हू कि उन का मार्केट रेट जरा देख लिया जाय। जरा यह बाजार मे चले जाय और वहा अपनी कीमत पता लगाए कि वहा उन्हे क्या मिलता है ? मैं चव्हाण साहब से कहूगा कि वह उन से कहे कि जरा बाजार मे जाय और देखे वहा क्या मिलता है ? अगर कोई 800 रुपये पाने वाला ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जरा हिम्मत के साथ बाजार मे जाए और जा कर वहा देखे कि उस मे क्या मिलता है तो 400 रुपये भी उसे नही मिलेंगे । वह तीन घटे भी काम नही करता, । दो घटे भी काम नही करता । एक कागज लेता है, उस मे तीन चश्मे पलटता है । कुछ नही है, यह खाली लोग है जिन्हे केवल अपना कैरियर बनाना है इन्होंने हमारी कमाई पर अपना कैरियर बनाना सीखा है । इन का कैरियर बने, इन के बच्चे अच्छे बने यह इन्होंने सीखा है और जो सरकारी कर्मचारी गरीब है उन लोगों की हालत बिगाड दी ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से ये लोग अपने घरों में काम लेते हैं। एस० पी० के घर में पाच सिपाही काम करते हैं, आठ सिपाही काम करते हैं—यह क्या है ? ये शोषण करने वाले लोग हैं और शोषण कर के अपनी जिन्दगी को बिताते हैं।

इसलिये समाज को आगे बढाने के लिए हम को कुछ सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे । बड़ी बड़ी तन्खवाहों को नीचे लायें और नीचेवालों को ऊपर उठाये—तब यह फर्क दूर हो सकेगा ।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): It is quite clear that Members on both sides of the House, irrespective of party affiliations, have expressed their almost unanimous opinion that none of them have been satisfied with the outcome of the recommendations of the Third Pay Commission The Third Pay Commission Report has come as a great disappointment to the Central Government employees. It was appointed 3 years ago and it was given broad-based terms of reference. It aroused vast expectations in the minds of the Central Govt employees They expected that the unjust anomalies and disparities would be removed and that some thought, some concrete suggestions would be given in regard to the much—talked about need-based minimum wage It is not as if it is a new phenomenon. This proposal of need-based minimum wage was discussed and accepted at the Fifteenth Labour Conference where in the Government was also a party. At that time the Labour Minister was Shri Gulzarilal Nanda. He was a party to this report The Government later on, after the agitation of the Central Government employees, included in the terms of reference examination of the proposal of

[Shri Sezhiyan]

need-based minimum wage. If it is not possible to give the need-based minimum wage of Rs. 314, certainly, the Members who have spoken on the other side have accepted that the present recommendation of Rs. 185 is very much below, far below, than even the minimum wage that could be calculated by any norm. It is not a question of inadequacy, it is not a question of paucity of funds. More than that, it is a question of injustice, it is a question of growing disparity which has come in, thanks to the recommendations of the Pay Commission.

It has been pointed out by the previous speakers that better scales of pay are available in other industries like steel, sugar, banking and coal; in addition, those employees in those industries are entitled to get a minimum bonus of 8 1/3 per cent. It is high time that Govt. gave a second thought to this aspect of the minimum wage for the Government employees also.

Mr. Daga who spoke previous to me pointed out that when you are crying so much and pleading for the Government employees, what about those poor people who live in the countryside, persons who do not get one square meal a day. But, that is quite beside the point under discussion. This Pay Commission was specifically appointed to go into the pay scales of the Govt. employees and to talk about some other thing, to divert the attention, will not be solving the problem at all. If the Government are quite convinced that unless and until the lowest strata of society in the villages are given higher standard of living and there is no use in having pay commissions, etc. they should put aside all these things and go in and try to remove the poverty in the villages. Therefore, at this stage, to come and say that Government employees do not work even for four hours or five hours, that they don't deserve anything, etc. shows only your own inefficiency, that you are not able to control them. Therefore, that will not be any argument at all to deny them,—to deny the lowest strata of Government employees,—their due.

Sir, about the Planning Commission, it is often said that, thanks to its role in planning, the rich people have grown richer while the poor became poorer. The same thing can be said about the Pay Commission also. In every Pay Commission's report, those who are in the higher echelons in the Government are getting more and more but for those in the lowest strata their real income is going down.

Among those who are doing the same kind of work and wielding same kind of responsibility, there is a growing class-consciousness in so far as they treat the I. A. S. cadre far above the science and technology cadres. So, when we talk of giving priority to the science and technology in our planning and development, we have not given the same status due to them in the matter of pay structure and status. In contrast with the position the I. A. S., Class I people of the scientific and technical service occupy a low and inferior position both in respect of pay scales and in respect of career prospects. Instead of bridging the gap between these two, the Pay Commission has widened the gap and pushed up the I.A.S. scale only. Here I am not only talking about the maximum and minimum pay that has been fixed but we should also look into the maximum and minimum pay scales and see how far a person who enters the I.A.S. service and a person who joins the Government service as a technologist or scientist is able to go up.

If you take the distribution of the employees in government service, of those who are in the I.A.S., as much as 30.5 per cent are above Rs. 2,000 pay band, and about 75 per cent of the IAS are above Rs. 1,100 grade. That means, a person who joins the I A.S. is sure to go to the top level of more than Rs. 2,000.

If we take a medical man who has joined the Government, we find that about 20 per cent of them are to be content with and end with their service with a grade of Rs. 1,100. For the

[Shri Sezhiyan]

engineering service also, it looks as if as much as 85 per cent of them has to remain and retire from Government service with the grade of Rs. 900—1100. The same thing can be said about the scientific and non-technical people. There is this disparity. Among the arguments advanced in the Pay Commission Report are that the district responsibilities are onerous for the I.A.S. people with the field experience which is crucial to policy-making and that export advice should be tested with the vast experience acquired in various areas of administration.

We should also find out how far and how long an IAS officer works in the field. I think that after four or five years, he comes back to the Secretariat. Bulk of the IAS cadre you will find not in the field but in the Secretariat—in the chosen headquarters. But, if we take an engineer or a medical officer, more than anybody else, they do the field service in remote and uninhabitable places. I do not know why the same kind of treatment and patronage should not be given to them. In other words, I do not want to under-estimate the importance to be given to the I.A.S. cadre to attract the best brains in the country to that service. But, at the same time, I do not also want the other services to go uncared for. Without overemphasising the importance of one undertaking or the other, I think some parity should be arrived at between these two classes. From the States, there has been a representation and a demand to increase the quota of promotion to the IAS in the States from 25 to 40 per cent.

That has been examined by the Pay Commission also. Though they have not given a decision, they accepted the principle that it should be more than 25 per cent. I understand the Home Ministry is having this matter under consideration and I hope they will bestow favourable decision.

Regarding pension matters, I would make a request to the Home Minister. Though the Pay Commission have recommended increases in the scales of pension and raised the overall ceiling for pension, the benefit starts only from a later date. The existing government pensioners should also get the benefit of these concessions. We have sent a petition also to the Finance Minister and he has been kind enough to assure us that he would consider it. Pension is not an *ex gratia* payment, but a deferred service benefit. The Pay Commission did not consider the case of the existing pensioners because they thought it fell outside their terms of reference. Government should give consideration to the appeal of the pensioners.

As for the effective date, when the Pay Commission was appointed, it was clear from the Government Resolution that it referred to all employees serving on date of appointment of the Commission and not on the date of submission of the Report. The First Commission took one year, the Second Pay Commission, I understand, took two years and the Third Pay Commission has taken three years. I do not know; the Fourth Pay Commission may take four years. The benefit should be given irrespective of the time taken. If they had submitted their Report on 31st December 1972, then those who retired on 1st January would have benefitted, but because the Report was delayed for no fault of the retiring persons, they should not be penalised.

Therefore, two aspects should be taken care of. What was the date of appointment of the Commission? It was March 1970. This should be given with effect from that date. Whenever a wage board goes into a question of temporary relief, the date is relevant. In this case, the date of temporary relief was 1st March 1970. So the implementation of the Pay Commission recommendation regarding pensioners should be from that date.

Apart from that, the existing pensioners also should get the benefit. The DA should be calculated for pensioners on the pension amount on the same

[Shri Sezhiyan]

terms as is calculated on the basic salary of an employee. That will take care of that.

Regarding scales of pay, it is a well known fact that at a time when unemployment is at its zenith for the educated as well as the uneducated, one can hope to get into service at the 25th year leaving him about 33 serviceable years only. During the tenure of service, all of them cannot get into higher grades. Further, the present grades are overlapping one another, especially after ten years and benefits on promotion are hardly worth counting. Hence the grades should be so rationalised that on promotion there should be a reasonable minimum difference of Rs. 30/- between the grade and the promotional grade

Regarding encashment of leave, some State Governments give this facility of conversion of life-over earned leave, of average pay leave and half-pay leave into cash, at the time of superannuation or premature death. This is paid to the employee or his nominee. I hope Government will give due consideration to giving this facility to the Central Government employees too.

There are many other small points I wanted to touch on, wherein the differentiation is very much. I will quote two instances. In ordnance factories the grade of Supervisor 'A' (Rs. 205—280) and that of Supervisor 'B' (Rs 150—240) are being merged into a single grade Rs. 380—540. In the Central Government service, grades of Rs. 205 – 280 have been revised to the scale Rs. 425—700 Why this differentiation between the two? I do not know why there is differentiation. There seems to be another kind of differentiation also based on the office you work. A Stenographer working in the All India Radio and a Stenographer working in the Central Government are getting different scales of pay. A driver in the All India Radio gets a pay which is different from the pay that a driver in the Central Government Secretariat gets. What is the principle behind this differentiation? It should not depennd upon the office where a person works.

The Minister has assured that the Government would take a final decision, about the two different classes of Income Tax officers after the report of the Pay Commission had been received. Now that the report had been received, it is hightime that a decision is taken as recommended by the Public Accounts Committee.

There is no use in asking the Central Government Employees or the workers not to go on strike and bandh. They indulge in these things only as a last resort. Before freezing the strike and bandhs, before freezing the wages, Government should try to freeze inflation and the rising prices in the country. It will be the only answer to the growing agony in this country.

DR. KAILAS (Bombay South): Mr Chairman, Sir, before I comment on the Third Pay Commission Report, I would like to examine the basis on which this Commission has sent its recommendations. Has the Pay Commission cared to see the resources of Central Government and demands thereon such as Development Planning, Defence and National security, the repercussions on the State Governments, Public Sector Undertakings, local bodies etc? Do the Commission's recommendations suggest that the Government should be a model employer so that its role as prime regulator of wage policy for the entire country and the responsibility to secure for all workers a living wage assumes a moral content and effectiveness? Has the Commission tried to work out and suggest what I.L.O, several committees, commissions, Courts and Tribunals have upheld namely the principle that the minimum need wage should be paid? Has the Pay Commission suggested wages commensurate with the level of per capita national income or consumption in the country? The Report in my opinion has not done justise to these questions.

The annual per capita income in 1971-72 was Rs. 660/- and the average index was 253. The lowest pay of Rs. 185/- suggested by the Third Pay Commission is great injustice to the employees.. The Government is committed to the policy of garibi hatao and removal of unemployment.

17.49 hrs.

[SHRI SEZHIYAN *in the Chair*]

The Pay Commission has not taken into consideration this national objective. I trace past history, let us take the Mahalanobi's Committee recommendations. This Commission has revealed that 10 per cent of the population was poorer at the end of Second Plan than in 1950. It further said that the top 5 per cent households earned more dividend income from share dividends but in spite of high progressive taxation policy, urban income and wealth got concentrated. The National Council of Applied Economic Research in 1962-63 showed that the top one per cent of household enjoyed 10 per cent of the total income while the bottom 15 per cent of the household claimed only 4 per cent of the national income.

The Reserve Bank survey reveals that poverty has increased from 52 per cent in 1960-61 to 70 per cent in 1967-68. It seems history is going to be repeated by the report of Third Pay Commission. Maybe planning has apparently done little to reduce inequalities of income and wealth, but definitely the Pay Commission has also its part to play. The disparity between the richest and the poorest has been almost 1.30 while we are committed to bring it down to 1.10. The result of the Second Pay Commission was that Government had to give increase in DA or interim relief 16 times. This Pay Commission also has recommended three interim reliefs—one on 1st March 1970, second on 1st October 1971 and third on 1st August 1972. If the Government accepts the recommendations of this Pay Commission, I am sure at least 12 times increase in DA will have to be given, if not 16 times. It is difficult to conjecture how many times relief may have to be given to the employees.

I know the salaries and wages bill of the Central Government on regular employees rose from Rs. 417 crores in 1960-61 to Rs. 1186 crores in 1970-71 and the number of employees also increased from 20.94 lakhs to 28.51 lakhs during these 9 years. It is also to be noted that the increase in the total wages and salaries bill of the Central Government has not been commensurate with the increase either in revenue expenditure or revenue receipts. The result is that a large section of the Government employees did not receive their due share of the increase in the national product, though the Government was over vigilant. Class IV employees got about 95.2 per cent. But I am very much concerned that Class III, Class II and Class I employees were not neutralised as they should have been. We are very much concerned about Class II and Class III employees who form the backbone of Government employees. It is very unfortunate that Class III employees got only 51 to 74 per cent neutralisation and Class II got only 25.4 per cent neutralisation. Class I employees got roughly about 16 7 per cent neutralisation.

Today we and the employees are agitating for justice in deciding the structure of pay and DA. All agree that there should be "equal pay for equal work", fair wage or minimum wage or need-based wage as is enunciated in article 39(d) of the Constitution under Directive Principles. But the level of wages and salaries which is feasible for profitable industries to achieve is beyond the reach of Government. We cannot compare Government with the private sector. But the employee does not distinguish between the two; he is only interested in how much he gets, whether from the public sector or private sector. When the private sector is paying so much and the Government cannot pay that much, naturally there is dissatisfaction and the employees demand a need-based pay or

[Dr. Kailas]

pay which should get them at least minimum comforts of life.

When we are considering all this, we should also see that inflation does not come in due to such a high rise of the pay scales because then a vicious circle will set in which will be difficult to cut. Government should consider very carefully whether to accept the recommendations of the Third Pay Commission as they are or they should revise them so that they need not have to face dissatisfied workers in the near future.

Why should the minimum not be commensurate with the level of *per capital* national income or consumption in the country? This should be taken as an indication to guard against undue wage increases The annual *per capita* income in 1971-72 was about Rs. 660 and hence the minimum remuneration should be Rs. 350, and not Rs 185 as has been suggested if we wish to bring in the ratio of 1.10.

We are committed to reduce the disparity between the highest and the lowest paid employees. While the disparity in United States was 6.7 per cent, in Australia 9.6 per cent and Ceylon 25.3 per cent, in India it was 25 8 per cent In India the ratio should be brought down to 1.10 at the earliest.

I feel that the Government will have to examine the recommendations of the Pay Commission very carefully and see that dissatisfaction does not set in the Government Servants. I hope Government will take a decision before it is too late. Whatever Government may decide as a model employer, the benefits of the recommendations of the Pay Commission should accrue to the employees from 1st March, 1971.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय मुझे गलत न समझा जाय तो मैं बड़े अदब के साथ इस तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मजदूर विरोधी मानता हूं आप कहेंगे कि इस का कारण क्या है कारण साफ है आप शुरु से देखेंगे तो पायेंगे कि जितनी ऊंची तनख्वाह पाने वाले हैं उन में बढ़ोतरी ज्यादा रिकमेंड की गई है और नीची तनख्वाह वालों के लिये कम बढ़ोतरी की गई है जो कि हमारे सिद्धान्त के खिलाफ है तथा समाजवादी समाज बनाने के लिये हमारे आदर्श के प्रतिकुल बजाय इस के कि यह डिफरेंस कम हो, वह और बढ़ा है इसलिये मैं इसे मजदूर विरोधी मानता हूं हमारे इस कथन से कुछ लोगों को इनकन्वीनियेंस हो सकती है, हम मानते है कि बड़े बड़े जो गिने चुने लोग है उनको थोडी दिक्कत होगी लेकिन ज्यादा लोगों की सुविधा के लिये हम को ज्यादा से ज्यादा कठोर कदम उठाना होगा। वैसा पे कमीशन ने नही किया है इसलिये मै इस को मजदूर विरोधी मानता हूं।

इस संदर्भ मे मैं रेलवे के एक वर्ग का उदाहरण दूगा और वह है गार्डों के बारे मे आप जानते हैं कि रेल के कानून की किताबों मे गार्ड ट्रेन का इन्चार्ज माना जाता है। उन की जवाब देही बहुत है। उदाहरण के तौर पर वह

1. Captain of the ship

2. Punctual running of the trains, prevention of thefts in trains;

3. supervision over the whole staff connected with the operational work of the trains;

4. दुर्घटना के समय आफिसर इन्चार्ज ऐट दी साइट आफ दी एक्सीडेंट होता है।

5 यात्रियों की सुविधा को देखने वाला वही एक आदमी है। पैसन्जर एमेनिटीज में जो चीजें आती है उन सारी चीजों के लिये हम उसी को जवाबदेह समझते हैं। प्रोटेक्टर, इन्फार्मर, इजीनियर, सभी कुछ वही होता है। और अन्त में;

6 फाइनल चैकिंग अथौरिटी भी है।

रेलवे गार्ड की जवाबदेही बराबर बढ़ रही है, जिस तरह से ट्रेन्स का डीमालाइज हो रहा है गाडियों मे डिब्बे ज्यादा लगते जा रहे हैं उसी के अनुसार गार्ड की जवाबदेही भी बढ़ रही है।

अंग्रेजो के समय मे गार्ड का बहुत ऊचा स्थान माना जाता था, उन को सुविधाये भी ज्यादा दी जाती थी। 1947 से, जब से हमारी सरकार आयी इस सदर्भ मे मे तीन, चार बाते कहना चाहता हू जिन से मालूम होगा कि किस तरह से उन के साथ बेइन्साफी की गई है। 1947 मे गार्डस का स्केल आध्रे पे 80–170 होता था, ड्राइवर का 80–170 और ए० एम० एम० 60–170 के स्केल मे होते थे। इसके बाद 1956 मे रिविजन हुआ। उसमे गार्ड का स्केल रखा गया 80–170। 1959 में गार्ड को 130–225 का स्केल दिया गया जबकि ड्राइवर को 150–240 का और ए० एस० एम० का 130–225 पर गार्ड के बराबर रखा गया। 1969 म गार्ड का रहा 130–225 रहा, ड्राइवर का 150–240 रहा और ए० एस० एम० का 150–240 हो गया। ए० एस० एम० का तो बढा दिया गया लेकिन गार्ड का वही 130–225 रखा गया। श्रीमान जी, जिसकी जवाब देही इतनी ज्यादा है क्या उसको आप इतने कम पैसे देगें ?

18.00 hrs.

थर्ड पे कमीशन की रिपोर्ट को आप देखें सभी वर्ग जिन की तनख्वाह 130 रुपये से शुरू होती थी उनकी 330 कर दी गई इस मे केवल गार्डस को छोड दिया गया और कहा गया है कि उनकी तनख्वाह 290 से शुरु हो। टी० सी० ई० की 130–212 को 330–560 रिकोमेंड किया गया है शंटिंग मास्टर्ज का स्केल जो 130–200 था उसके वास्ते 330–480 रिकोमेंड किया गया है एकाउंट्स क्लर्क का 130–300 से 330–560 रिकोमेंड किया गया है जबकि गार्डस का 130–225 से केवल 290–480 ही रिकोमेंड किया गया है। उनके साथ बहुत बेइन्साफी हो रही है यह इसी से पता चल जाता है।

इन सब बातों को देखते हुए भारत के बीस हजार गार्डों और ब्रेकसमैन ने एक महीने का नोटिस दे कर दस जून 1973 से वर्क टू रूल मुवमेंट शुरु करने का निश्चय किया। लेकिन माननीय उप रेल मंत्री के लिखित आश्वासन पर कि 'गार्डों के साथ न्याय किया जाएगा" उन्होने दस जून, मूवमेंट को डैफर कर दिया मैं चाहता हू कि आप इसके बारे मे कुछ करे और उनके साथ जो बेइन्साफी हुई है उसको दूर करे

थर्ड पे कमिशन ने गार्डस को जो कम दिया है उसके लिये यह जस्टिफिकेशन है कि उनको ओवर टाईम दिया जाता है स्पेशल कम्पेंसेटरी एलाउन्स दिया जाता है शार्ट ट्रिप एलाउंस दिया जाता है बांच आफरेस्ट एलाउंस दिया जाता है, रनिंग रूम फैसिलिटीज आदि दी जाती हैं लेकिन ये सब फैसिलिटीज प्रशासनिक हित में उनको जब भारत आजाद भी नही हुआ था उस समय से दी जाती है टी टी ईज इत्यादी को भी रनिंग रुम की सुविधाए मिलती है। टी ए मे या उनके रनिंग एलाउंस आदि में कोई बढोतरी नही की गई है। आपने स्वय माना है कि महगाई हो गई है इस लिए भी मैं चाहता हूं कि गार्डों की पे रिवाइज होने चाहिए और उसी तरह से होनी चाहिए जैसे दूसरे लोगों की हुई है।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव]

कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि जितनी पे आपने दूसरी समकक्ष केटगरीज के लिए रखनी है उतनी आप इस कटेगरी के लिए भी रखें।

आश्चर्य तब लगता है जब हम देखते हैं कि कंडक्टर जो एक डिब्बे का इंचार्ज होता है तथा उसके साथ एटेंडेंट भी रहता है उसकी भी तनख्वाह गार्ड जो पूरी ट्रेन का इंचार्ज माना जाता है उससे ज्यादा रिकोमेंड की गई है। लगता है कि बोर्ड पे कमिशन के अध्यक्ष श्री रघुवर दयाल तथा कमिशन के अन्य सदस्यों ने इस गार्ड वर्ग पर ध्यान नहीं दिया है वर्ना किसी भी आदमी के सामने यदि ये बातें रखी जाएं तो वह कनविंस हो जाएगा और इनको मान लेगा।

कमिशन ने अपनी रिपोर्ट के वाल्यूम चार, पेज 117 पर यह माना है :

"The Commission have adopted, as a guiding principle, that the duties and responsibilities of a post or of a series of posts encadred in the Service should be the primary factor determining the pay scale for that post or service."

रेलवे गार्डस की ड्यूटीज क्या है, उनकी रिसपांसिबिलिटीज क्या है, उनको जानते हुए भी उनका ग्रेड सब से नीचे रखा है। क्या यह खेदजनक बात नहीं है ? मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

एक और भी बात कमीशन ने कही है पेज 108 पर :

"The supervisor had to be paid a scale which is higher than the person who is supervised."

सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करता है उसको ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिये बजाए उसके जो सुपरवाइज्ड हैं। उसके बावजूद भी सब से कम ग्रेड गार्ड का रखा गया है, जो ट्रेन का इंचार्ज है। इसका क्या जस्टिफिकेशन है।

कमिशन ने माना है कि ग्रेड्ज की संख्या जो बहुत ज्यादा है उसको कम किया जाए। एक तरह के काम के लिए एक तरह की तनख्वाह उसने रिकमेंड की है। इसी आधार पर ए एस एम और टी० टी० ई० के लिए दो ग्रेड रिकमेंड किये है। परन्तु गार्ड के लिए तीनों ग्रेड रिकमेंड किए गये है, ए बी और सी। यदि उनके भी दो ग्रेड कर दिए जाए तो हम समझते हैं कि यह दिक्कत दूर हो सकती है क्योंकि समान कार्य के आधार पर बी और ए एक ग्रेड हो सकता है।

मैं प्रार्थना करता हूं कि गार्डज के लिए जो स्केल रिकमेड किए गए है उस पर फिर से विचार किया जाए और उनको माडिफाइ किया जाए। इस ओर रेल उप मंत्री ने जून के अपने पत्र में इशारा भी दिया था।

मैंने एक केटेगरी का उदाहरण दिया है। लेकिन वास्तव में जो भी नीचे की केटेगरी के लोग हैं, जो भी पेड कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। मैं चाहता हूं कि उनके पे स्केल पर फिर से विचार किया जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए और ऐसा करने के बाद ही कमिशन की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट किया जाए।

SHRI K. S. CHAVDA (Patan): Mr. Chairman, Sir, the eagerly-awaited report of the Third Pay Commission is at long last out. There is a proverb in Gujarati

'खोद्यो डुंगार अने काढ्यो उदुर ।'

which means, if I may say so, the proverbial hill has given birth to a mouse. Every government employee is dissatisfied with the recommendations made in the report. I have a feeling that the report is going to create many headaches to the Government.

I have cursorily gone through the report and I would like to bring to the notice of the Government certain disparities and anomalies. There is a disparity in the pay scales recommended by the Pay Commission. In the case of Class IV service, the increase in pay scale is 8.8 per cent, in the case of Class III service the increase is 4.5 per cent, in the case of Class II service the increase is 19 per cent, in the case of Under Secretary 11.1 per cent and in the case of other officers 14.7 per cent. This disparity should be rectified by the Government.

There is disparity in the case of pension also. The increase in pension given to low income group, below Rs. 1,800 per month, is to the extent of ten per cent, whereas in the case of higher income group, above Rs. 1,800 per month, the increase is 48.1 per cent.

Similarly, there is disparity in the case of gratuity also. The increase in the gratuity of low salaried people is 11.5 per cent while in the case of higher salaried people it is 25 per cent.

These disparities also should be rectified by the Government.

Regarding anomalies, take, for example, the case of railway signallers. Signallers are not the persons who down the signal; they are railway telegraphists. I say this because signallers are commonly understood to be those persons who do the work of lowering down the signal. Their main demand is that there should be parity with P. & T. telegraphists in regard to pay scales and promotion prospects which has been rejected by the Third Pay Commission. One of the grounds for rejection is that the period of training for P. & T. signallers is 9 months as against the 3—6 months training for the railway signallers. It is wrong to say that the period of training for the railway signallers is 3—6 months only. On the contrary, it is one month more than the period of training for the P. & T. men. For example, the training period for the railway signallers is: 3 months for Hindi telegraphy, 6 months for English telegraphy and one month for promotion course which includes higher technical. The Commission has not been properly briefed in this case by the Railway Ministry. That much I can say.

The second ground for rejection of parity is that the minimum requirement for the P. & T. people is 20 words per minute as against 18 for the railway signallers. The speed is 20 words when the Railway signaller in the initial grade crosses the basic pay of Rs. 118 in the grade of Rs. 110—200 that is, after two years of service. In the case of the railway signallers the railway messages are full of code words, obliques, brackets and so on while the P. & T. messages are very simple. The third ground for rejecting the demand for parity is that the P. & T. telegraphists have to deal with public messages. This is also incorrect. In the case of the railway signallers they have to deal with quite a lot of public messages as also the railway messages and the railway messages are very very long. Sometimes they have to work as Ticket collectors, as announcers and as clerk to the Station Masters and so on. Therefore, it seems to me that the Commission has not appreciated the quantity and quality of the work turned out by the railway signallers. Therefore, the conclusion drawn by the Commission that there should not be parity of railway signallers and the P. & T. telegraphists is erroneous and, therefore, I should request the Government that the railway signallers should be put on par with the P. & T. telegraphists. In the same way the peons of the Railway Telegraphs should also be put on par with the messenger of the P. & T.

[Shri K. S. Chavda]

Now a word about the pensioners. I would like to draw the attention of the Government to paragraph 2 of Chapter 67 which reads as follows:

> "We have also given thought to the question that the recommendations on pensionary benefits should be given some retrospective effect. As indicated in Chapter I the Government has announced that it would consider grant of relief to the existing pensioners in the light of the retirement benefits recommended for serving Government employees."

Therefore, the Government is under an obligation to give some relief to the existing pensioners. The prices are going up and up and these poor pensioners are also feeling the pinch of the rising prices. Therefore, the Government should announce at the earliest the relief to be given to the existing pensioners They should not be ignored because they are not in a position to form unions and resort to strike and put the Government into difficulty

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : सभापति महोदय, तीसरे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे वेतन-निर्धारण के सम्बन्ध मे कुछ आधार रखने की चेष्टा की है । उदाहरण के लिए उस ने नीड-बैस्ड मिनिमम वेज की चर्चा की है और उस के निर्धारण के लिए कुछ आधार अपनाने का प्रयास किया है । इस सम्बन्ध मे मांग की गई है कि मिनिमम वेज 314 रुपये होनी चाहिए, जब कि कमीशन ने 185 रुपये निश्चित किये है ।

लेकिन वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे जिन आधारों का डिसकस किया है, उन पर वह चला नही है । हमारी समझ मे यह बात आ सकती है कि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है कि मिनिमम मिनिमम वेज की मांग की गई है, वह हम नही दे सकते हैं । छोटे कर्मचारियों को जो 185 रुपये दिये जा रहे हैं, वे उस पर संतोष कर सकते हैं, करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए । लेकिन उन को टीस उस समय होती है, जब वे देखते हैं कि जो आदमी उन्ही के समाज मे पैदा हुए है, लेकिन जिन को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे साधन और अवसर प्राप्त हो गये, उन को 700 रुपये से 3500 रुपये तक का वेतन मिलता है, जब कि वे स्वय 250 या 300 रुपये तक भी नही पहुच सकते है । छोटे कर्मचारी सोचते है कि क्या उन की मिनिमम आवश्यकताओ इतने उचे वेतन पाने वाले लोगो के समान है या उन से कम है ।

मै समझता हू कि वेतन आयोग का एक खास मुद्दा यह होना चाहिए था कि हमारे समाज मे आज जो डिसपैरिटीज है, उन को खत्म किया जाये । लेकिन वेतन आयोग ने इस तरफ ध्यान नही दिया है । कल प्रधान मत्री ने कहा था कि किसान को यह समझना चाहिए कि उस को आज गेहू की कीमत कम मिलती है और अगर उस को अधिक कीमत मिलेगी, तो उस मे इनफलेशन होगा । यह बात हम समझ सकते हैं लेकिन हम ने ये जो व्हाइट एलिफेंट्स पाल रखे है, जिन का हम 3500 रुपये तक तत्खवाह देते है, उन का अधिकतर खर्चा लक्सरी आइटम्ज पर होता है और वास्तविक इनफलेशन उनकी वजह से होता है । आवश्यक चीजो पर उन का खर्चा बहुत कम होता है । जिन चीजो को हम आवश्यक नही कह सकते है, उन पर वे अधिक खर्च करते है और इस से इनफ्लेशन पैदा होता है । उस को चैक किया जाना चाहिए । मेरी

मान्यता है कि हमारे देश मे किसी भी अधिकारी को, सरकारी नौकर को, 1500 रुपये से अधिक तन्ख्वाह नही मिलनी चाहिए। ऐसा करने पर ही हम छोटी तन्ख्वाह पाने वालो के दिल की टीस को मिटा सकते हैं। हम नीचे की सैलरी को कायम रख सकते हैं, हम 400 या 500 रुपये का वेतन रख सकते है, छोटे कर्मचारी 185 रुपये पर ही सतोष करेगे, लेकिन सरकार ऊपर वालो को नीचे लाये। जब तक वह ऐसा नही करेगी, तब तक छोटे कर्मचारियो को सतोष नही होगा।

यह कितनी बडी डिसपैरिटी है कि आई० ए० एस० की सैलरी 700 रुपये से स्टार्ट होती है और वह 3500 रुपये तक जाती है और छोटे कर्मचारी 185 रुपये से शुरू हो कर 250 या 400 रुपये तक भी नही पहुच सकते हैं। वेतन आयोग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

वेतन आयोग ने परिवार की आवश्यकताओ के आधार को स्वीकार किया है। जहा तक शिक्षा पर किये गये खर्च का सम्बन्ध है, हम स्वीकार करते है कि जिस आदमी ने शिक्षा पर खर्च किया है उस को उस का थोडा बहुत कम्पेन्सेशन मिले। लेकिन हमारे देश मे शिक्षा किस आधार पर दी जाती है? आज हमारा समाज ही शिक्षा का खर्च बर्दाश्त करता है। स्टैट एक्सचेकर ही यूनिवर्सिटीज और कालेजो को रन करता है। चूकि कुछ लोग हाई नी प्लेस्ड है, इस लिए उन को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया है। लेकिन यह समाज की देन है। इस का मतलब यह नही है कि चूकि उन्होने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है, इस लिए वे समाज की कीमत पर पनपते रहे और उन को ऊचे वेतन मिलते रहे। समाज इस को बर्दाश्त नही कर सकता है।

जितनी तन्ख्वाह दी जाये, उस के हिसाब से काम भी लिया जाये, वेतन आयोग ने इस सिद्धान्त को बिल्कुल नजरअन्दाज कर दिया है। यह बहुत आवश्यक सिद्धान्त है, जिस के अनुसार सरकार को वेतन निर्धारित करने चाहिए।

हमे देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की मिनिमम आवश्यकताये कितनी है। आप एक सफाई कर्मचारी को ले लीजिये। जब वह काम कर के घर लौटता है, तो क्या 185 रुपये मे वह साबुन से अपने कपडे साफ कर सकता है और नहा सकता है अपने को डिसइनफैक्ट कर सकता है? व्यक्ति की मिनिमम आवश्यकताओ को देखना चाहिए था लेकिन ऐसा नही किया गया है।

अलग अलग विभागो म फर्क रखा गया है। मैं डीटेल्स मे नही जाना चाहता हू, लेकिन मै खास तौर से डिफेस सर्विसिज के बारे मे निवेदन करना चाहता हू। डिफेस सर्विसिज मे दो प्रकार के लोग है एक सिपाही के रैंक के और दूसरे आफिसर के रैंक के। आफिसर रैंक के लिए 400–700 रुपये की तन्ख्वाह रखी गई है। हमारे देश के रक्षको और सीमा के प्रहरियो ने बहुत अच्छा काम किया है और अफसरो की जो तन्ख्वाह बढाई गई है, हम उसका स्वागत करते हैं।

[श्री शिवनाथ सिंह]

लेकिन उस के साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि उस सात सौ के अंदर उन को आवश्यक कटौती कितनी करानी पड़ती है ? जो लेफ्टिनेंट रैंक का या मेजर रैंक का आदमी होता है उस को 500 रुपय के करीब करीब कम्पल्सरी डिडक्शस कराने पड़ते हैं । उस में उस को कुछ बचता नहीं है । इस और भी ध्यान देना चाहिए। यह जो मेस का खाना है या और इस तरह की चीजें हैं जो ब्रिटिश काल की फौजी परम्परा से हमें देन मिली है उस के हिसाब से डिस्क्शस उस को कराने पड़ता हैं । वह कम किए जाने चाहिए ।

दूसरी तरफ जो एक साधारण सिपाही उस की तनख्वाह हम ने क्या रखी है ? मिनिमम 185 रुपया हम मान कर चल हैं लेकिन सिपाही के लिए वह मिनिमम भी आप ने गारंटी नही किया है । वह मिनिमम भी उस को देने की सिफारिस नही है की और 165 से उस का वेतन शुरु किया गया है जो सवा दो सौ के आस पास तक जाता है । यह आर्गूमेंट दिया जाता है कि सिपाही के लिए खाना मुफ्त मिलता है, रहने की जगह मुफ्त मिलती है । दूसरी सहूलियत भी उस की हो सकता है । मिलती हो, लेकिन इस को भी देखना चाहिए कि सिपाही की डयूटी कितनी हार्ड है । और वेतन आयोग का दृष्टिकोण, मैं निवेदन करना चाहता हूं कितना उन के लिए दुर्भावनापूर्ण है, उन्होंने कहा कि सिपाही चाहे कितना भी ट्रेन्ड हो हम उस को स्किल्ड नही मान सकते हैं, हम उस को सेमी स्किल्ड की कैटेगरी में रखते हैं । आज सिपाही का कितना टेकनिकल और स्किल्ड काम है, अगले को गोली मारना है, अपने को डिफेंड करना है और कितने कितने इम्प्रूव्ड हथियार उन को चलाने पड़ते हैं, कितना टेकनिकल उन का जाप हो गया है और उस को आप स्किल्ड भी नहीं मानना चाहते । तो आज हमें कहते हुए दुख होता है नहीं कहना चाहते पर कहना पड़ता है कि यह वेतन आयोग या जितने भी आयोग बेठते हैं उस में उन लोगों के प्रतिनिधि बैठते हैं, जो ऊचे क्लास से आते है । आज फील्ड में वह जायगा जिस के आगे राम नही लगता, जिस के आगे सिह नही लगता, जिस के आगे शर्मा या वर्मा नही लगता जो किसान से आता है मजदूर से आता है आदिवासी और शेडयूलकास्ट से आता है वह लोग मरने के लिए जाते है, उन का प्रतिनिधि कोई नही बैठता और यह उन लोगो को टीस है कि वे लोग हमारी भावनाओ को, हमारी कठिनाइयो को नही देखते । आज वेतन आयोग ने कहा कि किस की कितनी जिम्मेदारी है उस को देखना चाहिए, किस की ड्यूटी कितनी हार्ड है इस बात को हमें देखना चाहिए । लेकिन सिपाही की डयूटी आप ने कहा देखी ? वह हिमालय की चोटी पर बर्फ से पड़ा रहता है जगलों मे पड़ा रहता है साप और बिच्छू का रात दिन सामना करता है । उस को वहा रहने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल आसमान के नीचे रहता है । लेकिन उस की तरफ आप ने ध्यान नही दिया और कह दिया कि उस को खाना मुफ्त मिलता है । खाने का भी एस्टीमेंट लगा लीजिए । जो सिपाही मेस में खाना नहीं खाता है उस को 2 रुपये 35

पैसे प्रति दिन के हिसाब से पेमेंट आप करते हैं। तो 2 रुपये 35 पैसे प्रति दिन के हिसाब से 365 दिन का उस के साथ और ऐड कर दीजिये। एक सिपाही अपने स्थान से से हजारो मील दूर बारह महीने पडा रहता है। दूसरे जो फोर्थ क्लास एम्पलाईज है मैं यह नही कहता कि उन को अधिक मिलता है, उन को और भी अधिक मिलना चाहिए, लेकिन वह अपने घर की देखभाल कर सकते हैं, दूसरा सबसिडियरी धन्धा कर सकते हैं, अपनी खेती देख सकते हैं, मवेशी पाल सकते हैं, लेकिन एक सिपाही जो फौज मे रहता है कोई दूसरा धन्धा नही कर सकता है, अपने घर की देखभाल नही नही कर सकता है और उस के बाद भी उस के साथ से इतनी हार्ड शिप आप करते हैं। इसलिए 185 रुपया जो मिनिमम रखा है दूसरो के लिए वह कम से कम उन के लिये भी 185 रुपया मिनिमम रखना चाहिये। मैं समझता ह कि माननीय वित्त मत्री जी इस मे कोई रुकावट नही करेगे। यह कहा जा सकता है कि जो लडाई के अग्रदर हमारे सिपाही या फौजी अवसर खत्म हो जाते हैं उन के परिवारो की देखभाल के लिये पिछले दिनो मे हमने बहुत कुछ किया है। लकिन वह तो जो लड़ाई मे मरते हैं उन के लिए आप करते हैं और लड़ाई मे मरने वालो की सख्या, उनकी परसेंटेज कितनी आती है और जो बाकी सिपाही हैं सब की परसेंटेज कितनी है, उस को देखना चाहिये और उसके हिसाब से उनका मिनिमम कम से कम 185 करना चाहिये। मै एक बार पुन. निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरे के लिए 185 रुपये मिनिमम रखा है वह मिनिमम 185 रुपये उन के लिए भी करनी चाहिए। हो सकता है कि 185 आज की हालत में कम हो, हम अधिक नही बढा सकते हैं तो आम वर्कर इस का स्वागत करेगा लेकिन ऊंचा वेतन पाने वाले जो हैं उन की तनख्वाह जब तक कम नही करेगे, तब तक नीचे वालो को सतोष नही होगा।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़): जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं वह बहुत गभीर ह और जैसा कि मुझ से पहले बोलने वाले कई वक्ताओ ने कहा इस मे राजनीति घुसेडना या पार्टियो के सवाल को घुसेडना यह एक अनुचित बात ह। श्री वाजपेयी जी ने कई बाते बहुत अच्छी कही, लेकिन उन सब का प्रभाव मेरे दिल से उतर गया जब वह इस अवसर को इस बात के लिए उपयोग मे लाए कि प्रधान मत्री के लाल किले के भाषण का उपहास उडाए और यह साबित करने का कोशिश करे कि शायद उन का दल सोने का है और बाकी पीतल के है। परीक्षा बहुत दफा हो चुकी है और जब जब उन के दल ने सत्ता सभाली है बडे बडे सिद्धातो की बात जो उन्होने कही उन मे से कितना वह अमल में ला सके और क्या कुछ कर के दिखाया? इस बात की परीक्षा लोगों के सामने हो गई कि वह सोना हैं या पीतल हैं। तो ऐसी बाते इस विषय के भीतर लाना मैं समझता हू कि बहुत अनुचित बात ह और इस समय जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं इस की गंभीरता को भंग करना ह।

[श्री अमर नाथ विद्यालंकार]

18.27 hrs.

[MR SPEAKER *in the Chair*]

यह मामला बहुत देर से चल रहा था और हमारा जो मजदूर वर्ग है, कार्य करने वाला वर्ग है, सरकारी कर्मचारी है, बहुत देर से वह इंतजार मे थे कि पे कमिशन की रिपोर्ट निकलेगी और उन को कुछ राहत मिलेगी। इस समय इस सदन मे जो भाषण हुए है उन से आप को मालूम हो गया होगा कि सदन के अधिकाश वक्ता असन्तुष्ट है जो कुछ पे कमिमीशन ने इतने लम्बे अरसे के बाद और इतना इतजार कराने के बाद मे रिपोर्ट दी है उस से। आम तौर पर कर्मचारी भी उस से असतुष्ट है और सदन के सभी दलो के लोग भी उस से असतुष्ट है।

मै समझता हुं कि शायद यही कारण है कि मत्री महोदय बहुत जल्दी बात का फैसला नही कर पाए कि पे कमीशन की सिफारिशो कहा तक माने और कहा तक न मानें। अगर आप तफसील मे जाएगे तो आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा एनामलीज और इतने ज्यादा काट्रेडिक्शम उन्होने पैदा कर दिए, इतनी परस्पर विराधी बातें उन्होने कही है, मैं तफसील मे नही जाना चाहता क्योकि समय बहुत कम है, लेकिन आप जितना देखेंग उस के अदर इतनी परम्पर विरोधी बाते उन्होने कह दी है कि इस समय उन की सिफारिशो को लागू किया जाय तो शायद मुक्नलिफ तबको मे सवाल पैदा किए जाएगे कि यहा पर वह एनामलीज है, वहा पर यह एनामलीज है। कारण उस का मैं ऐसा समझता हू जिस का जिक्र अन्य वक्ताओं ने भी किया कि जो भी मजदूर वर्ग में काम करते है और जो भी समाज को एक नई दिशा में चलाना चाहते है उन की तरफ से बार बार यह माग हुई है कि हमे एक नीति मुकर्रर करनी चाहिए वेजेज की और प्राइमेज की। क्या मजदूर वर्ग को हम किस दिशा मे जाना चाहते है, उस को किस स्टेटस पर रखना चाहते है इस के सबध मे हम ने कोई निश्चित नीति बनाई है? अगर पे कमीशन के सामने ब्राड आउटलाइन्स रख दी जाती कि हमारी ये नीतिया है और आप को जो निर्णय करना है इन नीतियो को देखते हुए उस के मुताबिक निर्णय करना है तो शायद पे कमीशन की रिपोर्ट ज्यादा बेहतर होती। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि अगर आप फर्स्ट पे कमीशन को देखें, सेकेंड पे कमीशन को देखें और थर्ड पे कमीशन को देखें तो उन के सामने कोई एक रूपरेखा अपनी नीतियो की हम ने नही रखी है। नतीजा यह होता है कि हरएक पे कमीशन अपने स्टैंडर्ड, अपने नार्म्स मुकर्रर करता है, अपने उसूल बनाता है और उस के मुताबिक कोई न कोई रैकमडेशन दे देता है। हमे मजदूरो के सबध मे एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए, नार्म्स बनाने चाहिए और वह पे कमीशन के सामने चाहिए थे कि यह हमारी रूपरेखा है, इस के अदर इन लाइन्स पर आप विचार करें तो शायद पे कमीशन की रिपोर्ट बेहतर हो। लेकिन वह नीति उन के सामने हम नही रख सके, देश के सामने नही रख सके, एक राष्ट्रीय नीति कि कहां तक हम नीड-बेस्ड वेजेज चाहते हैं, नीड-बेस्ड की बात हम

कहते हैं तो उस के क्या माने हैं , इन तमाम चीजों को हम साफ साफ उन के सामने रखना है, फिर कोई कमीशन उस का फैसल कर सकता है । जैसा मैंने कहा कि मैं तफसील मे नही जाना चाहता, दो तीन बातें लेकिन मैं कह देना चाहता हु ।

डागा जी ने जो कहा ओवर टाइम के सबंध से मैं उस से सहमत नही हू । उन्होने कहा कि हमारे वर्कर्स काम नही करते । अगर उन का इशारा क्लास फोर और क्लास थर्ड के वर्कर्स की तरफ था तो मै समझता हु कि यह बहुत गलत बात है । हमारे क्लास फोर और क्लास थ्री के वर्कर दिन रात काम करते है और सारा बोझ उठाते है, सारा काम वही चलाते है । अगर उन का इशारा कुछ बडे बडे आफिसरो के सम्बन्ध मे था, तब तो ठीक है । हमारे यहा एक कहावत है कि घोडा सवार घोडा सवार को पहचानता है । जहा आफिसर काम करता है, वहा लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते है । लेकिन जहा आफिसर मुश्किल से दो-तीन घन्टे काम करे और जब पता किया जाय तो मालूम होगा कि मीटिंग मे बैठे है, वहा चाय पी रहे है, इस से वर्कर्ज पर क्या असर पडेगा ? उन को हिदायतें नही मिलती है जिस मे वे बैठे रहते है । यह बात बिलकुल ठीक है कि काम थोडा होता है, लेकिन इस का कारण यह है कि ऊचे अफसर समय नही देते, काम की तरफ पूरी तवज्जह नही देते, वे सारी जिम्मेदारी दूसरो पर छोड देते हैं । नीचे से जो नोट जाता है, उस को डिटो कर के भेज देते हैं । पहले उन से यह आशा की जाती थी कि जो भी नोट फाइल पर उन के सामने नीचे से आयेगा, सैक्रेटरी उस पर जरूर कुछ लिखेगा । बल्कि पहले तो ऐसा नियम था कि सैक्रेटरीज खुद सेल्फ-कन्टेन्ड नोट बनाते थे और जिम्मेदारी की राय देते थे, लेकिन अब ऐसा नही होता है । अगर ऊपर से जिम्मेदारी का अहसास हो तो नीचे उस का असर पडता है ।

एक बात की तरफ खास तौर से मैं मत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हू—हमारी यूनियन टैरिटरी चण्डीगढ मे कुछ कर्मचारी है जो सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मुलाजिम है । पहले दूसरे और तीसरे पे-कमीशन ने कहा था कि जो सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मुलाजिम है, उन को एलाउन्स देने के लिये जो नजदीक की टैरिटरी होगी, उस मे जो भत्ता दिया जायगा उसी के मुताबिक उन के लिये निर्णय किया जायगा । चण्डीगढ मे जो यूनियन टैरिटरी के मुलाजिम है जो पजाब और हरियाणा के मुलाजिम है, उन को जो कम्पेन्सेट्री एलाउन्स मिलता है वह वहा के सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मुलाजिमो को नही मिलता है । यह मामला कई सालो से चल रहा है । पहले उन को मिलता था लेकिन जब 1965 मे पाकिस्तान के साथ लडाई हुई तो उस एलाउन्स को थोडो दर के लिए बन्द किया गया, इस लिये कि देश पर कष्ट था । उस के बा पजाब, हरियाणा और यूनियन टैरिटरी के मुलाजिमो के लिये तो जारी हो गया, लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मुलाजिमो के लिये जारी नही कियागया । मै समझता हू कि इस विषय म मत्री महोदय को फैसला करना चाहिये और सही फैसला करना चाहिये, उन के साथ जो विषमता है उस को दूर करना चाहिये । इसी तरह से मै समझता हू कि जो सैन्ट्रल गवर्नमैट के मुलाजिम है, जो वहा पर काम करते है उन को और

[श्री अमर नाथ विद्यालंकार]

सहूलियत भी मिलनी चाहिय, जो नजदीक के इलाकों में मिलती हैं ।

दूसरी बात मैं पेंशनरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं—आज मंहगाई भत्ता मुलाजिमों को मिलता है, लेकिन पैन्शनरो कुछ नही मिलता । उन की हालत बहुत ज्यादा खराब है । इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये, आज जो कीमते बढी हैं, उस का असर पेन्शनरो पर भी पडता है, इस लिये इस असर को दूर करना चाहिये और उन को जो पेन्शन मिलती है उस से रिबीजन होना चाहिये ।

आखरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि सरकार काफ़ी देर तक इन्तजार करा चुकी है, अब सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि इस का जल्द से जल्द फैसला हो । मै यह सुझाव दूगा कि पे-कमीशन की रिपोर्ट आप के सामने है, तमामा लोगो ने—वर्कर्स ने, पार्टियो ने, ट्रेड यूनियन्ज़ ने इस को स्टडी कर लिया है । उन्होने कहा है कि सरकार एक-एक चीज़ को लेकर उन के साथ अच्छी तरह से बात करे और जल्द से जल्द उन बातो का फैसला किया जाय । सरकारी मुलाजिमो की बातो का भी समझा जाय और जहा जहां उन को एतराज है, उन को अच्छी तरह से देख कर तथा जिस रास्ते पर वह देश को चलाना चाहते है, उस को ध्यान मे रखते हुए फैसला करे । क्योकि जिस रूप मे पे कमीशन की रिपोर्ट आई है, ऐसा जाहिर होता है कि उस से किसी को सन्तोष नही है । अगर इस को वैसे का वैसा मान लेगे तो इस से सन्तोष नही होगा और कई तरह की नई पेचीदगिया बढ़ेगी ।

MR. SPEAKER: I am told that the Finance Minister was to be called to speak at 6.45 p.m.

SHRI PILOO MODY: Provided I finish.

MR. SPEAKER: There are some others also; if you were the only one it does not matter.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): I will require about five minutes.

MR. SPEAKER: Then, five minutes each.

SHRI PILOO MODY (Godhra): Sir, after a long time, after 3 years of waiting, the Pay Commission has finally produced a report. I would remind the House that much before the third Pay Commission was appointed, for years a demand has been generated because of increase in prices and I think it took a year or two for the Government to finally come round to the point where it would appoint a Pay Commission. The Commission sat for three years—looking at the results, I do not know what they were doing. They submitted this report about six months back and this Government is still examining it. I think it would be interesting to note that in the total period of time between when the need for a third Pay Commission arose, which I would put at 5 years ago, and the time that the Government makes up its mind which is still quite indefinite,—something that only an astrologer will be able to tell us We all realise that prices in this country have moved up so sharply and I do not understand under what terms of reference or what period of time or what the Pay Commission had in fact recommended which would be anywhere approximating the conditions that prevail today. I suggest that the third Pay Commission report may be left as it is and that the fourth Pay Commission be appointed right away so that maybe at some point of time, we would be able to catch up in this race between salaries and prices.

The Pay Commission sat in judgment on the future of 29 lakhs of people, not

counting the army and it has left all of them dissatisfied. The only category of people which I think with some justification are not dissatisfied is the very privileged class of IAS officers, who work closely together with another privileged class, namely, the ministers. I have heard a lot of talk by members from the Congress benches trying to protect this Government on points which are totally indefensible. Take for instance the increase in non-productive expenditure. Has the Finance Minister ever carried out a survey of the percentage increase year by year of productive *vis-a-vis* non-productive expenditure? If he had carried out that exercise, he would have realised that all the money he sucks out of the people year after year when he presents the budget is being siphoned off in non-productive expenditure, which is resulting in a great deal of unemployment, which is resulting thereafter in prices rising due to shortages, which thereafter result in Pay Commissions being appointed, which thereafter result in greater salaries being demanded and by the time the result comes, the prices have again gone up! I want to know how he is going to catch up in this spiral. I would like him to spend five minutes out of six minutes of his reply to answer this question how he is going to end this vicious circle. I believe that the Government of India, in spite of its incapacities, must have an answer to this question, because unless there is an answer to this question there is no point in your governing. You have to realise how you are going to break this vicious circle, this inflationary spiral which you have got into as a direct result of the policies that you have been pursuing, in spite of the advice that we have been giving you. I would like to know how it is going to be done. You have taken the advice of my comrades on this side for so many years and each time you have jumped into a deeper ditch. I think it is time for you to reverse the trend and start taking some sensible advice for a change, if at all you are prone to any advice.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: We will make you the centre of the vicious circle.

SHRI PILOO MODY: It is only by remaining in the centre of a vicious circle that one escapes getting into the spiral. You are in the spiral. I am out of it.

Another suggestion was made that the relationship in salaries should be 10.1. But there must be some rationalisation about this. The Finance Minister gets a monthly salary of one lakh of rupees. So also his other Cabinet colleagues. If I take that particular example and give one-tenth of his salary to a newly-recruited class 4 staff, he would receive a monthly salary of Rs. 10,000.

This is the way I would like Shri Vajpayee and others to look upon this ratio of 10:1 that has been suggested. So, let us not take this to absurd lengths. We cannot have people who are enjoying a salary of one lakh of rupees a month to think seriously whether a person should get Rs. 150, 175 or 233 a month.

I do not know what the terms of reference of the Pay Commission were. But if the report is any indication that they had a terms of reference, I can only say that it is totally unrealistic to the conditions that prevail today. I do not see any serious discussion having taken place, for instance, in evolving a minimum wage, or a minimum pay scale or a need-based wage. It is something that should have been evaluated in terms of our political aspirations. After all the *garibi hatao* that we have been going through for the last three years, this is what the Pay Commission recommends, namely, Rs. 185. They themselves say "it should have been Rs. 314, but let us be realistic and make it Rs. 196." Thereafter, they recommend Rs. 185. Is it any wonder that everybody around the country is saying "Oh God, give us back our poverty of three years ago". This is the end result of the *garibi hatao* campaign that the country is yearning for its poverty of three years ago. When this is the manner in which the Pay Commission has decided on a wage bill, I do not know what the Govern-

[Shri Piloo Modi]

ment is considering. It should have rejected this and should have accepted that the Pay Commission has scientifically worked out as the minimum wage.

But, then, I ask you, where will the Finance Minister get the money? The reason why they have been stalling for the last six months on deciding, considering, looking into and what not over the Pay Commission Report is the fact that he does not have any money. The treasuries are empty and the Nasik Press is over-tired. The fact of the matter is that we have become a bankrupt nation..... (*Interruptions*) Let them all squat and lay golden eggs because no other method has been left to them.

This is what I said last time also. It is a refusal to face reality; it is a refusal to accept mistakes; it is a refusal to see the situation as it exists. But you go on with words trying to fool yourselves that you are a very healthy body and that you are a very healthy economy. Where is the money to come from? Does anyone of you know? There is only one place and that is the Nasik Press. The moment you touch the Nasik Press. I warn this House that the minimum wage will jump to Rs. 600.

Another thing is that there has been no proper job evaluation done by the Pay Commission. There is not only no job evaluation but no basis of calculating the values for services exchanged. How is it possible to arrive at a bureaucratic structure of grades and go on revising it without any job evaluation? It is meaningless. Has any job evaluation been done by the Ministries as to why they need so much staff? We have something like 20 lakhs of people whose sole purpose in life, from morning to night, is to inhibit the progress of this country and to obstruct everything that is happening in this country. Nyet Nyet, Nyet—'No' to everything.

To supply one piece of information, you ask the person to fill up 20 forms. You take a simple procedure like admitting a guest in the Gallery of the Lok Sabha. You know how many signatures are required. This is a sort of mentality which requires more forms, obstructions, more signatures, counter-checking, etc. etc. with the result that in the end you spend everything that you earn in trying to support people who obstruct you from earning more.

There are a thousand anomalies in this Report. The most absurd of the anomalies of the pay structures is the so-called dearness allowance. By the very words, it implies that everytime there is dearness, the allowance must commensurate with the dearness. This is what the dearness allowance means. After 26 years of Independence, we have not adhered to the cost of living. Take the case of pensioners and ex-Servicemen. Nobody even listens to them. They are a forgotten lot in our life. The people who have served this nation loyally for 20 years, 30 years, 50 years, are just forgotten. Why? Because he does not have the money to pay. How can you just allow a large body of these people to be forgotten? There are several other anomalies that have already been mentioned here.

Take, for instance, the commercial clers. The people who do normal routine work have been given enhancement. But these people have not been given that. Take the Government employees' need-base wage calculated by the Pay Commission at Rs. 185. Actually, it is Rs. 340. Take, for instance, the veterinary doctors. The man who looks after a dog is treated worse than the dog itself. These are qualified people whose salaries are well below even the cost of the animals that they treat.

Then, take the instance of railwaymen and telegraph staff whose case my friend ably presented. The variations between their salaries and other like workers bear no relationship at all. Take the case of train examiners. The people who examine trains, the people who supervise the well-being of trains, the people who travel throughout the country, are paid less than those who actually go and knock down below.

The supervisors are paid less than the supervised. How long do you think that this country can go on with this sort of anomalies, with this sort of Pay Commission, with this sort of structure? Why do we not have a straightforward single structure where a man gets employed and he gets his regular increments and gets promoted to functional jobs, where he is utilised for the function for which he is placed there and full work is extracted from him and he is not allowed to spend six hours on drinking tea and two hours on obstructing the public? Why do we not think broadly in terms like these? I think, every single humanbeing in this country is entitled to what we call a need-based wage. But you think only in terms of organized industry. Mr. Daga was very right when he said that we think only about the organized sector of the country. Are those in the enormous unorganized sector not humanbeing? Are they not entitled to minimum facilities and wages? Are they not entitled to get at least the wherewithal at a price which they can afford?

When it comes to pumping more money into the agricultural economy, how can it be done? The moment fertiliser comes, Mr. Chavan taxes it. The moment somebody makes even a little progress—the Green Revolution which was nothing but a little rash, a little which—immediately it was heavily taxed. The entire agricultural sector which was not made to pay anything other than land revenue is taxed at every turn.

You should eliminate the duties on those items which are daily consumer needs and you should do that and do that quick and fast. When you bring an interim budget or Vote on Account, whatever it is called, do not come and ask for more money; come and say that you have decided to reduce these taxes and particularly the indirect taxes on items which are daily consumer needs. This will give relief to the whole nation, it will give relief to the farmer who is in the unorganized sector, it will give relief to the landless labourers, to the so-called underprivileged sections of society, it will also give relief to government servants, it will also give relief to IAS officers, and if Mr. Chavan goes to the bazaar, it will give relief to him also. You have to do what the Pay Commission has said and more. But let us think at this juncture of brining down the price structure. And there are very well known methods. If Mr. Banerjee and Mr. Indrajit Gupta cannot advise you correctly, take somebody else's advice.

MR. SPEAKER: There are only three or four names left. If they are prepared to forego their chance, it will be all right; I can call the Minister. But before that...

18.55 hrs.

ANNOUNCEMENT RE. APPOINTMENT OF A COMMITTEE OF PARLIAMENT TO CONSIDER THE QUESTION OF PAY STRUCTURE, ETC. OF THE STAFF OF RAJYA SABHA AND LOK SABHA SECRETARIATS

MR. SPEAKER: Hon. Members, I have to make announcement about my own Secretariat today.

The Third Pay Commission have not made any recommendations in regard to the Secretariats of Rajya Sabha and Lok Sabha.

The Chairman of Rajya Sabha and I have been feeling for sometime that some appropriate machinery should be devised to consider the question of pay structure applicable to the officers and staff of the two Secretariates. We have consulted one another and decided to appoint a Committee of Parliament consisting of the following members:—

1. Shri K. N. Tiwari, Chairman, Estimates Committee.
2. Shri Jyotirmoy Bosu, Chairman, Public Accounts Committee.
3. Shri Y. B. Chavan, Minister of Finance.
4. Shri K. Raghuramaiah, Minister of Parliamentary Affairs.